https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाई है'

वर्ष-13, अंक-13 01-15 जुलाई, 2018 (पाक्षिक) ₹20

International day of yoga 21st June

Yoga for Harmony & Peace

योग

विश्व को जोड़ने की अनुपम शक्ति

भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुस्तिकाएं जारी

क्या कांग्रेस विचारधाराविहीन है?

डॉ. मुखर्जी बलिदान दिवस पर विशेष

गुवाहाटी (असम) में 19 कैंसर अस्पतालों का शिलान्यास रखते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनवाल, टाटा ग्रुप चेयरमैन श्री रतन टाटा, असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा और अन्य

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करते मध्य प्रदेश भाजपा नेतागण

अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) में एक विशाल 'विकास यात्रा' रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) में सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह और अन्य

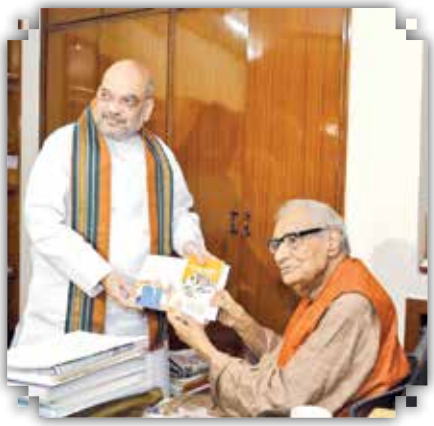

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्य सभा सांसद श्री कुलदीप नैय्यर से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत पूर्व न्यायाधीश श्री सीएस धर्माधिकारी से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत पूर्व न्यायाधीश श्री पीपी नावलेकर से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 संघर्षरत दुनिया को एकजुट करने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा योग: नरेन्द्र मोदी

चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को देश से लेकर विदेश तक, समुद्र से लेकर आकाश तक और रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक मनाया गया।...

वैचारिकी

माल, मांग और औद्योगिक प्राथमिकताएं 16

श्रद्धांजलि

रामचंद्र बैंदा / मोहम्मद अनवर 19

लेख

क्या कांग्रेस विचारधाराविहीन है? 20

सीधी भर्ती प्रक्रिया: एक जरूरी निर्णय 22

बंगाल-कश्मीर के लिए ऋणी हैं हम 24

अन्य

2014-18 में कोयला उत्पादन में 10.5 करोड़ टन की वृद्धि 14

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांझा किया अपना फिटनेस वीडियो 23

आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित 25

असम : 19 कैंसर अस्पतालों का शिलान्यास 26

खराब सुरक्षा स्थिति को लेकर भाजपा ने समर्थन वापस लिया 27

प्रधानमंत्री द्वारा नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र... 28

इंटरनेट कवरेज में 75% से अधिक की वृद्धि 30

संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी: नरेन्द्र मोदी 32

प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद 33

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

व्यंग्य चित्र 04

10 भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाई है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 10 जून को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला स्थित अंबिकापुर में आयोजित राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ विकास...

12 भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुस्तिकाएं जारी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 13 जून को विभिन्न विभागों/मोर्चा से जुड़े...

13 ट्रेन दुर्घटनाएं 118 (2013-14) से घटकर 73 (2017-18) हुईं

पिछले चार वर्षों में सरकार ने 'साफ नीयत, सही विकास' के दर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा...

15 नेफेड ने 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की रिकॉर्ड खरीद की

किसानों से दलहन, तिलहन और प्याज की उपज की खरीद करने वाली संस्था भारतीय...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

केंद्र सरकार ने ऐसी दुरुस्त व्यवस्थाओं की स्थापना की है जिससे गरीब लोगों को उच्चतम गुणात्मक स्वास्थ्य तक पहुंच मिल सके। यह हमारी सरकार है जिसने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत शुरू करने का सम्मान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम से 50 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा।

@AmitShah

आज पूरा देश राहुल गांधी से जानना चाहता है कि लश्कर-ए-तैयबा और गुलाम नबी आजाद के विचार एक समान कैसे हो जाते हैं...ऐसा क्या रिश्ता है? राहुल गांधी को तुरंत गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज जैसे अपने नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

@myogiadityanath

योग लोक कल्याण का माध्यम है, भारत की योग परम्परा मानवतावादी परम्परा है। योग संकीर्णताओं से परे है और मानवता को बढ़ावा देता है, जिन मार्गों और कार्यों से संतुलन मिल जाए, वही योग है, योग से अंदर की बुराइयों को दूर करने में मदद मिलती है।

facebook

वीरभूमि उत्तराखंड के जवानों की रग-रग में #NationFirst यानी 'स्वयं से पहले राष्ट्र' का भाव है। हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी सहित जिला स्तर पर को-ऑपरेटिव समूह बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे योजना के जरिए पूर्व सैनिकों को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी में भी एक आर्मी हॉस्टल बनाया जाएगा। जिसमें सैनिकों एवं उनके आश्रितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा प्रदान की जायेगी।

— त्रिवेंद्र सिंह रावत

माता वैष्णो देवी और भगवान अमरनाथ की भूमि जम्मू-कश्मीर सांस्कृतिक, भौगोलिक और संवैधानिक रूप से भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कांग्रेस ने धारा-370 और अलगाववादियों का समर्थन कर हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के खिलाफ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, वहां के कांग्रेसी नेता लश्कर-ए-तैयबा जैसे बयान जारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री की कश्मीर नीति के खिलाफ बोलकर पाकिस्तान का साथ दे रही है।

— सुशील कुमार मोदी

व्यंग्य चित्र

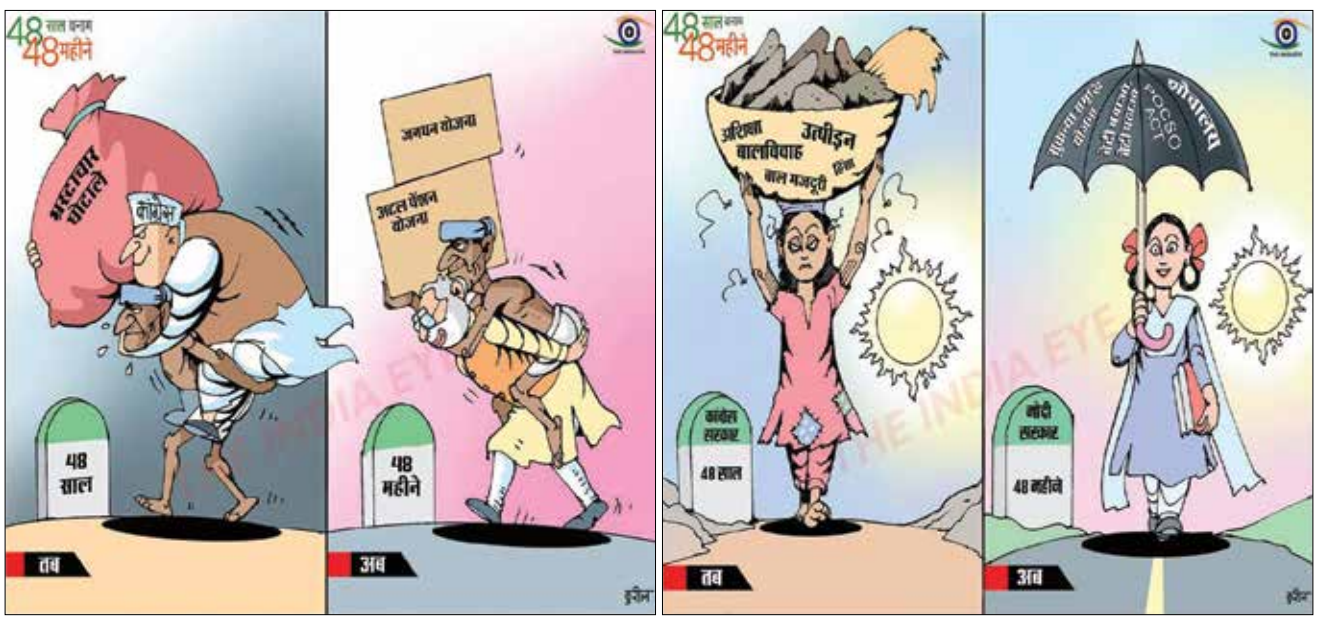

साभार : सोशल मीडिया

जम्मू-कश्मीर में शांति व विकास के स्थायी समाधान की आवश्यकता

आज जब राष्ट्र डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की पुण्यतिथि 23 जून तथा जयंती 6 जुलाई पर भारत माता के इस महान् सपूत को याद कर रहा है, देश पुनः अपनी एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए कृत संकल्पित है। स्वतंत्रता आंदोलन के महान् विरासत जन-जन के लिए प्रेरणा का पुंज तो हैं ही, परन्तु स्वतंत्रता के साथ-साथ जिन घटनाओं से देश का विभाजन हुआ, वे अब भी किसी न किसी रूप में देश के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा विभाजनकारी-सांप्रदायिक राजनीति के चलते जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, दुर्भाग्य से इसके हुक्मरान भारत से अंतहीन दुश्मनी को ही अपना मजहब मानते हैं। नेहरू तथा कांग्रेस शासन की कमजोर नीतियों से पाकिस्तान का हौसला लगातार बढ़ता रहा है और वह भारत के अंदर आतंकी-अलगाववादी तत्त्वों को बढ़ावा देने में संलिप्त रहा है। पिछले चार वर्षों में इन आतंकी-अलगाववादी गुटों पर कड़ी कार्रवाई कर हमारे वीर जवानों ने इनके हौसले पस्त कर दिये हैं और कई खूंखार आतंकियों का घाटी में सफाया किया जा चुका है।

भाजपा के लिये जम्मू-कश्मीर की जनता का हित हमेशा महत्त्वपूर्ण रहा है और पार्टी ने आतंकी-अलगाववादी गुटों के सामने जनता को एकजुट रखने के लिए कई संघर्ष किये हैं। यही कारण था कि चुनावों में जनता द्वारा दिये गये जनादेश के आधार पर भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाना स्वीकार किया था। जहां यह प्रयास किया गया कि राज्य की स्थिति सामान्य हो तथा लोग शांति एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, वहीं, पीडीपी नेतृत्व जनाकांक्षाओं को पूरी तरह नहीं समझ पायी। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी खराब होने लगी, जिस कारण भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने को बाध्य हो गई। हालांकि सुरक्षा बल अदम्य साहस का परिचय देते हुए अनेक आतंकियों तथा उनके महत्त्वपूर्ण कमांडरों का सफाया करने में सफल रहे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पीडीपी की नीतियों के कारण सुरक्षा-वातावरण में सेंध लग रही थी। इसके अलावा पीडीपी जम्मू एवं लद्दाख के लोगों में भी विश्वास पैदा नहीं कर पा रही थी, जिससे कि लोग सरकार से कटे हुए महसूस कर रहे थे। पीडीपी की घाटी-केंद्रित राजनीति के कारण वह दलगत-हितों से ऊपर नहीं उठ पायी तथा जम्मू एवं लद्दाख के लोगों को सरकार के कार्यों से नहीं जोड़ पा रही थी। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के पास प्रदेश की जनता के हित में समर्थन वापसी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था।

> कांग्रेस के वोटबैंक एवं तुष्टिकरण की नीतियों के कारण घाटी में विभाजनकारी तत्त्वों के हौसले बढ़े और वहां अलगाववाद की समस्या पैदा हुई। परन्तु अब नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में सुरक्षाबलों ने आतंकी गुटों के विरुद्ध अनेक सफलताएं अर्जित की हैं। एलओसी के पार जाकर 'सर्जिकल स्ट्राईक' के द्वारा हमारे वीर जवानों ने अपनी एक नई गौरव गाथा लिख दी है।

भारत की एकता एवं अखंडता भाजपा के लिए सर्वोच्च प्रतिबद्धता का विषय है और इससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने देश की एकता एवं अखंडता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की घुटनाटेक नीति का ही फल था कि 'अलग विधान, अलग निशान', कश्मीर में प्रवेश हेतु परमिट व्यवस्था और धारा 370 जैसे विषय स्वीकार किये गये। इससे घाटी में अलगाववाद का बीज पड़ा और देश को लम्बे समय से अलगाववाद की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जिन्होंने इन प्रावधानों के विरुद्ध विशाल जनांदोलन चलाये, उन्हें कश्मीर में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में वे बलिदान हो गए। भाजपा ने निरंतर अलाववाद के विरुद्ध संघर्ष कर पूरे देश में जनचेतना का निर्माण किया है। कांग्रेस के वोटबैंक एवं तुष्टिकरण की नीतियों के कारण घाटी में विभाजनकारी तत्त्वों के हौसले बढ़े और वहां अलगाववाद की समस्या पैदा हुई। परन्तु अब नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में सुरक्षाबलों ने आतंकी गुटों के विरुद्ध अनेक सफलताएं अर्जित की हैं। एलओसी के पार जाकर 'सर्जिकल स्ट्राईक' के द्वारा हमारे वीर जवानों ने अपनी एक नई गौरव गाथा लिख दी है। अब समय आ गया है कि शांति एवं विकास के लिये जम्मू एवं कश्मीर में स्थायी समाधान निकाला जाए और यह केवल नरेन्द्र मोदी जैसे मजबूत इरादों वाले व्यक्तित्व द्वारा संभव है। यही डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

संघर्षरत दुनिया को एकजुट करने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा योगः नरेन्द्र मोदी

चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को देश से लेकर विदेश तक, समुद्र से लेकर आकाश तक और रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक मनाया गया। सियाचिन में 21 हजार फुट की ऊंचाई पर 250 जवानों ने और समुद्र में नौसैनिकों ने पोत में योगासन किए। भारत में तीन विश्व रिकॉर्ड भी बने। इनमें छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में एक करोड़ लोगों ने एक समय में योग किया। कोटा में 1.05 लाख लोगों ने योग कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। अहमदाबाद में 750 दिव्यांगों ने एक साथ योग किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम 'शांति के लिए योग' है।

मुख्य कार्यक्रम देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में हुआ, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग 50 हजार लोगों के साथ योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास किया। इससे पहले श्री मोदी ने देश-दुनिया को योग की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि योग में संपूर्ण मानवता को जोड़ने का सामर्थ्य है। यह संघर्षरत दुनिया को एकजुट करनेवाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो व्यक्ति, समाज व राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है। इस बिखराव और विघटन को जोड़ने वाली शक्ति है योग। उन्होंने कहा कि योग ने दुनिया को 'इलनेस से वेलनेस' का रास्ता दिखाया है। यह प्राचीन होने के साथ ही आधुनिक भी है। योग के पास ही तमाम रोगों व परेशानियों का सटीक उपचार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहां-जहां उगते सूरज की किरणें पड़ रही हैं और प्रकाश दैदीप्यमान हो रहा है, दुनिया के उस भूभाग में लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। देहरादून से डबलिन तक, शंघाई से शिकागो और जकार्ता से लेकर जोहानिसबर्ग तक योग ही योग है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव सबसे कम रिकॉर्ड समय में स्वीकार किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि दुनिया में अपना सम्मान चाहते हैं तो अपनी विरासत का सम्मान करना सीखें। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल

यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया है। ग्लोबल फ्रेंडशिप को आज योग नई ऊर्जा दे रहा है।

योग का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यदि भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो घर में ही इस तरह का विरोध जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो बिखराव आता है। समाज में दीवारें खड़ी होती हैं। परिवार में कलह बढ़ता है। जीवन में तनाव बढ़ता है। उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया कि समाज और देश में सौहार्द कायम करने के लिए आपसी कटुता और वैमनस्य खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'अगर हमें हमारी शक्ति सामर्थ्य के प्रति भरोसा नहीं होगा, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर परिवार में परिवार ही बच्चे को हमेशा नकारता रहे और अपेक्षा करे कि मोहल्ले वाले बच्चे का सम्मान करें तो यह संभव नहीं।' एक तरह से मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा योग दिवस पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में यह तंज कसा।

पहली बार दो राष्ट्राध्यक्ष योग कार्यक्रम में एक साथ हुए शामिल

चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लातिन अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी परमारिबो में अपने समकक्ष श्री डेजायर डेलानो बेटरेसे के साथ योग आसन किए। यह पहला मौका है, जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में दो देशों के प्रमुख एकसाथ शामिल हुए। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने गोल गले की टी-शर्ट पहनकर दर्जनों लोगों के साथ आसन किए। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत से 14,000 किलोमीटर दूर पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति बेटरेसे के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर बेहद खुश हूं। हमारे साथ योग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने इस मौके को यादगार बनाया। राष्ट्रपति श्री कोविंद यूनान, सूरीनाम और क्यूबा के तीन देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में बुधवार को ही सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंचे। उधर, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद परिसर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भागीदारी की।

कोटा में 1.05 लाख लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

राजस्थान के कोटा में एक लाख पांच हजार लोगों ने एक ही स्थान पर योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में कोटा का नाम दर्ज करा दिया। बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की उपस्थिति में आरसीए मैदान में कोटा में पढ़ने आए देशभर के छात्रों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने सुबह साढ़े छह से सात बजे तक एक साथ योग कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम के बाद गिनीज की टीम ने मौके पर ही आयोजकों को प्रमाणपत्र प्रदान किया। अभी तक एक स्थान पर सबसे ज्यादा लोगों के योग करने का रिकॉर्ड मैसूर के नाम था। पिछले वर्ष योग दिवस पर मैसूर में एक साथ 55,524 लोगों ने योग किया था। विश्व रिकॉर्ड के अलावा तीन दिन से चल रहे योग शिविर में 10 हजार सूर्य नमस्कार एक साथ करने, 25 हजार पुशअप एक साथ लगाने सहित करीब 100 रिकॉर्ड बनाए गए। ये सभी रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं और साधकों को सर्टिफिकेट भी जारी हो चुके हैं।

एक ही समय पर समूचे छग में एक करोड़ लोगों ने योग कर बनाया रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में एक ही समय (सुबह सात से आठ बजे) पर राज्यभर के विभिन्न आयोजन स्थलों पर एक करोड़ लोगों ने योगाभ्यास कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्डस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्य आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अगुआई में हुआ।

'46 इस्लामिक देश दे चुके हैं योग को मान्यता'

राजधानी लखनऊ में चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गृहमंत्री श्री

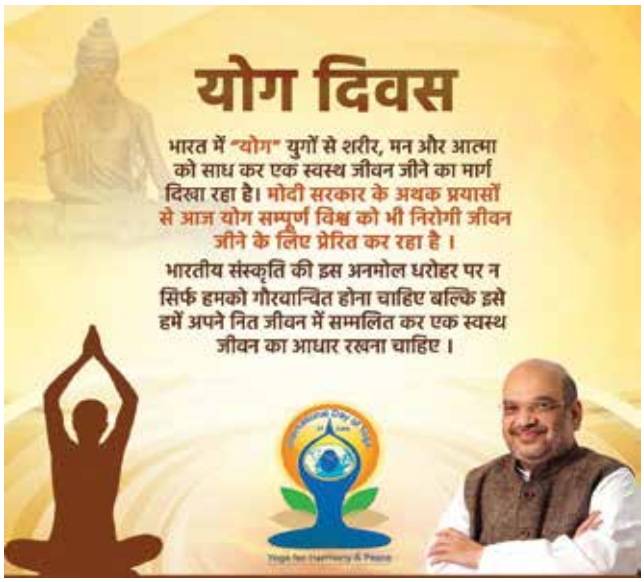

राजनाथ सिंह, राज्यपाल श्री राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में योग किया। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रीगण सर्वश्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। इस योग कार्यक्रम को आयुष विभाग ने आयोजित किया था।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योग का इतिहास बहुत पुराना है। पहले कहा गया कि योग एक धर्म से जुड़ा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 191 देश मान चुके हैं कि योग सभी धर्मों के लिए है। 46 इस्लामिक देश योग को मान्यता दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रगतिशील देश है। लेकिन अब वहां की लाइफ स्टाइल में भी योग शामिल हुआ है। कल्चरल डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री श्री मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल हुई है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में योग अपनाने से बीमारी पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। आधे घंटे का योग सबको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग की क्रियाएं सबके जीवनचर्या का पहले से ही हिस्सा हैं।

विश्व भर में रही धूम

दुनिया के कोने-कोने में सामूहिक तौर पर योग मनाया गया है। कट्टरपंथियों की धमकी के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के कई शहरों में योग करते लोगों की तस्वीरें वहां की मीडिया ने दिखाई है। मुस्लिम देश बंग्लादेश के भारतीय उच्चायोग के आयोजन में दस हजार स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने सूचना दी है कि उसने व्लादिवोस्तक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक योग आयोजन करवाने में मदद की है। बीजिंग स्थित इंडिया हाउस में योग करने के इच्छुक लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एजेंसियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि चीन के तमाम दूसरे शहरों में भी योग दिवस आयोजित किए गए। यूरोपीय संघ में जिस तेजी से योग की लोकप्रियता बढ़ी है उसे देखते हुए वहां के तमाम देशों में स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालयों का एक प्रमुख काम हो गया है कि वह योग दिवस का आयोजन करे। डेनमार्क जैसे देश में जहां योग कुछ वर्ष पहले तक बेहद सीमित था, अब तकरीबन आधे दर्जन शहरों में भारतीय दूतावास की मदद से इसका आयोजन हो रहा है।

यूएन उप महासचिव बोलीं– संयुक्त राष्ट्र के लिए पूरी तरह उपयुक्त है योग

संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव अमीना मोहम्मद ने कहा कि योग संयुक्त राष्ट्र के लिए 'पूरी तरह उपयुक्त' है और आज की जटिल दुनिया में जहां तनाव और भ्रम व्याप्त हैं वहां मस्तिष्क एवं शारीरिक तंदरूस्ती तथा शांति कायम करने में प्राचीन भारत का शारीरिक तथा मानसिक अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों, राजनयिकों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और बच्चों ने भाग लिया। संरा मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में रंगबिरंगे मैट बिछे थे जिन पर प्रतिभागियों ने दो घंटे के योग सत्र में विभिन्न योगासन किए। इस बार की थीम थी 'शांति के लिए योग'।

संरा उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने चौथी बार आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा, ''आज की दुनिया बहुत अधिक जटिल है। हमारे सामने मूल मूल्यों के क्षरण की चुनौती है, जीवन के हर चरण में तनाव है, भ्रम है, खासकर के युवाओं में। योग संस्कृत के शब्द 'योग' से लिया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।'' योग दिवस आयोजित करने के लिए भारत की सराहना करते हुए अमीना ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया।

संरा में भारतीय के स्थायी प्रतिनिधि श्री सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि योग की बढ़ती लोकप्रियता तथा वैश्विक स्तर पर इसे अपनाया जाना इस बात का संकेत है कि योग विभिन्न समाजों, आयु वर्ग, जाति तथा पेशे के लोगों के लिए लाभदायक है। यह व्यक्तिगत, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तथा व्यक्तिगत, सामाजिक शांति और समरसता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश चलाया गया। ■

चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में रही धूम

ढाका, बंगलादेश

सियोल, दक्षिण कोरिया

जानकी मंदिर, जनकपुर नेपाल

जोजोजी, जापान

सेंट पीटर्सबर्ग, रूस

पोरनीकेट, फ्रांस

भाजपा सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहाई है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 10 जून को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला स्थित अंबिकापुर में आयोजित राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ विकास यात्रा में शामिल हुए और इस अवसर पर आयोजित एक विशाल जन-सभा को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने अंबिकापुर में बसंत मल्टीप्लेक्स से पीजी कॉलेज ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो किया। सभा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह ने भी संबोधित किया। ज्ञात हो कि श्री रमण सिंह के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने के उद्देश्य से राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ विकास यात्रा शुरू की गई है। इस विकास यात्रा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह 18 दिनों में लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा और 45 जन-सभाओं के माध्यम से 50 विधान-सभा क्षेत्रों के 20 लाख से अधिक लोगों से जनसंपर्क करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े मनोयोग से विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रमण सिंह सरकार ने लगातार तीन कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ में विकास की जो अहर्निश यात्रा शुरू की है और उसे जिस तरह से समाज के हर वर्गों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, उससे यह निश्चित है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने राज्य की जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार सिर्फ विजय से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस बार 65 सीटों पर विजय के साथ सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी में यह ताकत नहीं है कि वे चुनाव से पहले ही अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की श्री रमण सिंह सरकार है जो चुनाव से पहले हर विधान सभा क्षेत्र में जाकर राज्य की जनता के सामने अपनी सरकार हिसाब-किताब दे रही है। उन्होंने कहा कि तीनों कार्यकाल में श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर झुकाना पड़े। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महान जनता ने लगातार तीन बार जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसका उपयोग कर रमण सिंह सरकार ने राज्य के हर घर में विकास और खुशहाली पहुंचाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूछते हैं कि मोदी सरकार ने चार सालों में क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि

हमने देश की जनता ने सेवा करने का मौक़ा दिया है, जब हम जनता से वोट मांगने फिर से जायेंगे तो अपने पल-पल का हिसाब उन्हें देंगे। जनता को अपने पल-पल का और एक-एक पाई का हिसाब देने की तो हमारी परम्परा रही है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमसे चार सालों के काम-काज का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो आपसे चार पीढ़ियों के काम-काज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक के समय में लगभग 55 सालों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, राहुल गांधी जी, आप बताइये कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो पाया। राहुल गांधी पर करारा प्रहार जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आखिर क्यों आजादी के 70 साल बाद भी देश की लगभग एक तिहाई आबादी के पास बैंक एकाउंट नहीं था, क्यों आजादी के 70 साल बाद भी देश के 10 करोड़ परिवारों के पास गैस सिलिंडर तक नहीं था, क्यों 10 करोड़ घरों में शौचालय भी नहीं थे, आखिर क्यों आजादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद देश के लगभग 19 हजार गांव अंधेरे में जीने को मजबूर थे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चार सालों में 30 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा, लगभग साढ़े तीन करोड़ से अधिक माताओं को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया, लगभग साढ़े सात करोड़ परिवारों को शौचालय दिया और बिजली से वंचित सभी 19 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया। उन्होंने कहा कि अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 1.4 लाख माताओं को फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का लक्ष्य रखा है, जबकि एक करोड़ लोगों को घर देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि इसमें से दो करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी, अब आप जवाब दीजिये कि आजादी से अब तक लगभग 55 साल तक आपके परिवार ने देश में शासन किया, लेकिन आखिर क्यों देश की जनता विकास को तरसती रही, क्यों स्कूल नहीं खुले, क्यों टीकाकरण नहीं हुआ, आपको 55 सालों का हिसाब देश की जनता को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आपके पास आयें तो आप उनसे चार पीढ़ियों और 55 साल का हिसाब जरूर मांगें।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पिछले चार सालों में औसतन हर 15 दिन में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई योजना लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सर्व-स्पर्शीय एवं सर्व-समावेशी विकास के लिए लगभग 116 योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस पार्टी की सोनिया-मनमोहन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास के लिए महज 48,000 करोड़ रुपये की राशि दी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर करने के लिए 1,37,927 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो यूपीए सरकार का लगभग तीन गुना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक सत्ता सुख भोगने के अलावा जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिन-रात बिना कोई छुट्टी किये अहर्निश देश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं राहुल गांधी आये दिन विदेशों में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, ये जनता की सेवा क्या करेंगे!

छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि रमण सिंह सरकार ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ की छवि को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ विकास यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब श्री रमण सिंह राज्य की सत्ता में आये तो छत्तीसगढ़ का बजट केवल 9,000 करोड़ रुपये का था, जबकि अब यह बढ़ कर 83,169 करोड़ हो गया है लेकिन कांग्रेस को राज्य का विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार की विदाई के वक्त राज्य की विद्युत् उत्पादन क्षमता महज 4,000 मेगावाट थी, रमण सिंह सरकार ने इसे 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला बिजली सरप्लस और बगैर पावर कट का राज्य कोई बना है तो वह छत्तीसगढ़ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाते समय विद्युत् पम्पों की संख्या सिर्फ 72,000 थी, जबकि अब यह बढ़ कर 4,50,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न उत्पादन महज 65 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर अब 1.03 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसी तरह हॉर्टीकल्चर प्रोडक्ट्स का उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1.02 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले धान का उत्पादन केवल 5 लाख मीट्रिक टन होता था, रमण सिंह सरकार ने इस 70 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी एक हजार किलोमीटर से बढ़ाकर 22 हजार किलोमीटर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रमण सिंह सरकार ने राज्य की साक्षरता दर को 60% से बढ़ा कर 71% किया है, एमबीबीएस की सीट संख्या को 100 से 1,100 किया है और जिला अस्पतालों की संख्या को भी 16 से बढ़ाकर 26 किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं में भी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है और उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और वीर जवानों के शौर्य के बल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया गया, जिससे दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में व्यापक बदलाव हुआ। ■

तेमजेन इमना एलोंग बने नागालैंड भाजपा अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 जून को नागालैंड के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री तेमजेन इमना एलोंग को भाजपा, नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री एलोंग भाजपा नागालैंड प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष श्री विसासोलि लहुनगु का स्थान लेंगे। श्री लहुनगु नागालैंड बांस विकास एजेंसी के अध्यक्ष तथा पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस के सह अध्यक्ष हैं।

भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुस्तिकाएं जारी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 13 जून को विभिन्न विभागों/मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्य के दूसरे चरण के लिए पुस्तिकाएं विमोचित की।

वर्ष 2015 में शुरू किए गए ''पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत भाजपा ने पहले ही लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है, जिसे राज्य, मंडल और बूथ स्तर पर आयोजित किया गया है।

विमोचन समारोह में बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि यह इतिहास में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का विश्व में सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिससे भारतीय राजनीति का स्तर ऊंचा उठेगा। पहले चरण में, पार्टी ने मंडल से जिला और राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और हमने इन स्तरों पर लगभग दस लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। दूसरे चरण में, पार्टी के मोर्चाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी श्री मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी विचारधारा, नवाचार, उद्देश्यों, पार्टी नीतियों तथा पार्टी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा तथा विशेष विषय से जुड़े तकनीकी पहलुओं के अद्यतन विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर आयोजित होगा अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य, जिला और मंडल स्तरों पर इनका आयोजन होगा। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तीन दिन का होगा वहीं राज्य, जिला और मंडल स्तर पर यह 2 दिन का होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा विश्व में सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी उभर कर आई है, जिसमें इसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ है और इसे एक विशिष्ट स्वरूप की पार्टी करार दिया गया है। यह पार्टी का दायित्व है कि वह ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता तैयार करें, जो राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान कर सकें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाएं और कार्य कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके।

कार्यक्रम के संयोजक श्री महेश शर्मा ने कहा कि 2014 में भारी जनादेश के साथ सत्ता में आने के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी में विस्तार, कंसोलिडेशन और प्रशिक्षण के तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। पहला 'महा सदस्यता अभियान' था जिसमें भाजपा ने 11 करोड़ पार्टी सदस्य बनाए। यह विश्व का सबसे बड़ा विश्व रिकार्ड रहा दूसरा 'महा सम्पर्क अभियान' था जिसमें सभी बनाए गए सदस्यों को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क किया गया। तीसरे कार्यक्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रकाशन महाभियान की शुरूआत की गई। विचार यह रहा कि मंडल से राष्ट्रीय सभी स्तरों तक पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण महाभियान के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में पार्टी ने देशभर में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। यह भी अपने तरह का नया रिकार्ड सिद्ध हुआ है।'' भाजपा राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग के अन्य सदस्यों में सर्वश्री आर. बालाशंकर, हेमंत गोस्वामी और सुनील पांडेय की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

ट्रेन दुर्घटनाएं 118 (2013-14) से घटकर 73 (2017-18) हुईं

पिछले चार वर्षों में सरकार ने 'साफ नीयत, सही विकास' के दर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को भारतीय रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया है। सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता हो गई है और इसके परिणामस्वरूप ट्रेन दुर्घटनाएं वर्ष 2013-14 के 118 से घटकर वर्ष 2017-18 में 73 रह गईं। इस तरह ट्रेन दुर्घटनाएं घटकर 62 प्रतिशत के स्तर पर आ गईं।

1 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) फंड को 5 वर्षों में सुरक्षा खर्च के लिए आवंटित किया गया है। असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए पिछले चार वर्षों में 5,479 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है। सुरक्षा में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों के तहत भर्ती के माध्यम से 1.1 लाख सुरक्षा पद भी भरे जा रहे हैं।

'नए भारत' के लिए बुनियादी ढांचे की नींव रखकर पूंजीगत व्यय में व्यापक वृद्धि की गई है। पिछले 4 वर्षों में औसत वार्षिक पूंजीगत व्यय, वर्ष 2009-14 के दौरान हुए औसत व्यय की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। रेलवे अत्यंत तेज गति से पूरे भारत को जोड़ रही है। नई लाइनों को चालू करने की औसत गति में 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 4.1 किमी (2009-14) से बढ़कर 6.53 किमी प्रति दिन (2014-18) के स्तर पर पहुंच गई है।

उन्नयन और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए बेंगलुरू उपनगरीय प्रणाली (2018-19 के बजट में 17,000 करोड़ रुपये) और मुंबई उपनगरीय प्रणाली (2018-19 के बजट में 54,777 करोड़ रुपये) हेतु व्यापक निवेश निर्धारित करने से भारत के शहरी क्षेत्रों में नियमित दैनिक यात्रियों की आवाजाही को काफी बढ़ावा मिला है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एचएसआर) गति, सुरक्षा और सेवा के माध्यम से भारत के परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। एचएसआर परियोजना से 'मेक इन इंडिया' संबंधी लाभों के अलावा रेलवे लातूर, (मराठवाड़ा) महाराष्ट्र; न्यू बोंगाईगांव, असम; लुमडिंग, असम; झांसी, (बुंदेलखंड) उत्तर प्रदेश और सोनीपत, हरियाणा में अनेक आगामी परियोजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर और आर्थिक विकास सृजित कर रही है।

रेलवे ने विद्युतीकरण में छह गुना वृद्धि के साथ टिकाऊ रेल परिवहन की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिया है। इसके तहत विद्युतीकरण को वर्ष 2013-14 के दौरान 610 आरकेएम से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 के दौरान 4,087 आरकेएम कर दिया गया।

रेलवे ने वर्ष 2017-18 में 1,162 एमटी और वर्ष 2016-17 में 1,107 एमटी की सर्वाधिक माल ढुलाई के साथ देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। माल ढुलाई आमदनी भी पिछले साल की तुलना में अनुमानित 12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2019-20 तक विभिन्न चरणों में समर्पित माल गलियारों (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर) के चालू हो जाने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा।

डिजाइन में स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देते हुए रेलवे एस्केलेटर, लिफ्ट, निःशुल्क वाई-फाई इत्यादि सहित आधुनिक सुविधाएं स्थापित करके स्टेशनों का रूप-रंग पूरी तरह बदलने समेत यात्री सुविधाओं को बेहतरीन कर रही है। मार्च 2019 तक 68 रेलवे स्टेशनों में सुधार लाया जाना निर्धारित है।

सरकार ने तेजस, अंत्योदय एवं हमसफर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करने समेत रेलगाड़ियों एवं रेल डिब्बों को काफी

सुधार दिया है। यात्रियों की यात्रा एवं आराम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए त्योहारी मांग पूरी करने के लिए 1.37 लाख रेल सेवाओं के साथ पिछले चार वर्षों के दौरान 407 नई रेल सेवाएं आरंभ की गई हैं। खान-पान (केटरिंग) भी रेलवे का एक फोकस क्षेत्र रहा है, जिसमें 300 से भी अधिक रेलगाड़ियों में खाने-पीने की सभी वस्तुओं पर एमआरपी की प्रिंटिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके साथ ही गुणवत्ता एवं स्वच्छता में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए बेस किचनों में भोजन बनाने पर करीबी नजर रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का उपयोग किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचे और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण अल्पावधि में समय के पालन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन लंबी अवधि में इससे त्वरित और सुरक्षित ट्रेन आवाजाही सुनिश्चित होगी। रनिंग समय को कम करके और नियोजित रखरखाव ब्लॉकों की अनुमति

देकर ट्रेनों की समय-सारणी बेहतर कर दी गई है। ट्रेनों में किसी भी देरी के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए 1,373 ट्रेनों पर एसएमएस सेवाएं आरंभ की गई हैं।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय रेल भी अपनी ओर से इसमें अहम योगदान दे रही है। साफ-सफाई, तीसरे या अन्य पक्ष द्वारा स्वतंत्र सर्वेक्षणों सहित स्वच्छता, एकीकृत मशीनीकृत साफ-सफाई की शुरुआत, बॉयो-टॉयलेट, गंदगी साफ करने के लिए ऑटोमैटिक रेल-माउंटेड मशीन, इत्यादि पर प्रमुखता के साथ फोकस रहा है।

भारतीय रेलवे ने डिजिटल पहलों और पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। ई-रिवर्स नीलामी नीति शुरू की जा रही है, जिससे लगभग 20,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिल सकती है। अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन में सरल अनुमोदन प्रक्रियाओं की बदौलत संबंधित प्रक्रिया में लगने वाली समय-सीमा 30 माह से घटाकर 6 माह हो गई है।

13 लाख से भी अधिक सदस्यों वाले रेल परिवार को सशक्त बनाने और उनका कौशल बढ़ाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए निचले स्तर पर अधिकारों को सौंपने या हस्तांतरण करने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

वडोदरा में भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय अगस्त 2018 में खुलने के लिए तैयार है। कर्मचारी सशक्तिकरण से लेकर कौशल बढ़ाने के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे अपने कार्यबल में एक नई ऊर्जा भर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे जीवन रेखा बन जाए और जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सके और 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ■

2014-18 में कोयला उत्पादन में 10.5 करोड़ टन की वृद्धि

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कोयला उत्पादन 2013-14 के 462 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 567 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसके कारण पिछले 4 वर्षों (2014-18) में कोयला उत्पादन में 10.5 करोड़ टन की वृद्धि हुई, जिसे हासिल करने में 2013-14 से पहले लगभग सात वर्ष लगे थे। उत्खनन के लिए खुदाई 2013-14 के 6.9 लाख मीटर की तुलना में लगभग दोगुनी बढ़कर 2017-18 में 13.7 लाख मीटर तक पहुंच गई। दरअसल, बढ़े हुए कोयला उत्पादन से 'सभी के लिए 24 घंटे किफायती बिजली' उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जो 2022 तक नवीन भारत विजन का एक हिस्सा है।

यही नहीं, पिछले चार वर्षों के दौरान विशिष्ट कोयला उपभोग (प्रति यूनिट बिजली के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा) में 8 प्रतिशत की कमी आई है जो साफ नीयत, सही विकास के सरकार के दर्शन को प्रदर्शित करता है। देश के कोयला क्षेत्र में सुधार ने ऊर्जा क्षमता, दक्षता एवं सुरक्षा बढ़ोतरी में योगदान दिया है। अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधार, वाणिज्यिक कोयला खनन उच्चतर निवेश एवं बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में सहायक होगा।

गौरतलब है कि 89 कोयला खदानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई और कोयला धारिता राज्यों को 100 प्रतिशत राजस्व के साथ आवंटित किया गया, जिससे खासकर, सामाजिक रूप से पिछड़े एवं आकांक्षी जिलों के लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में राज्यों को सहायता मिलेगी।

केंद्र सरकार ने कोयला एवं रेल मंत्रालयों के बेहतर समन्वयन के जरिये बेहतर माल ढुलाई पर भी फोकस किया है। कोल इंडिया का कोयला लदान 2014-15 के 195 रेक प्रति दिन से बढ़कर 2017-18 में 230 रेक प्रति दिन हो गया है। 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कोयला निकालने हेतु समयबद्ध कार्य निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। बिजली क्षेत्र में कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाने का परिणाम 3,359 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षमता बचत के साथ 55.66 मिलियन टन की कुल कोयला आवाजाही तर्कसंगतता के रूप में सामने आया है।

कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, चिर प्रतीक्षित टोरी-शिवपुर रेल लाइन (44 किमी) का एक हिस्सा, टोरी-बालूमठ रेल खंड आखिरकार 9 मार्च, 2018 को आरंभ कर दिया गया। ओडिशा में झारसुगुडा-बारापल्ली (53 किमी) रेल लाइन भी पूरा किया जा चुका है।

कोयला गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 'उत्तम' ऐप लांच किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के सभी खदानों का पुनर्श्रेणीकरण कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा किया गया है। ■

नेफेड ने 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की रिकॉर्ड खरीद की

किसानों से दलहन, तिलहन और प्याज की उपज की खरीद करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने वर्ष 2017-18 में 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की। इससे 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिला। किसानों के बैंक खातों में पैसे का सीधा हस्तांतरण हुआ है। इससे खरीद की व्यवस्था और सुदृढ़ हुई। नेफेड के व्यावसायिक आंकड़ों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और संकेत बता रहे हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में भी नेफेड रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने की दिशा में अग्रसर है।

गौरतलब है कि यह वही नेफेड है जो पिछली सरकार के दौरान मृतप्राय हुआ जा रहा था। नेफेड भारी अनियमितताओं के कारण वित्तीय संकट में फंसकर बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। नेफेड पर बैंकों की लेनदारी संबंधी मुकदमों की भरमार थी।

नेफेड ने पिछली संप्रग सरकार के चार वर्षों (2011-14) में किसानों से महज आठ लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद की थी। वहीं, इसमें 2014-18 के दौरान गुणात्मक तौर पर आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। राजग सरकार के कुशल नेतृत्व में किसानों से इन चार वर्षों में समर्थन मूल्य पर 64 लाख मीट्रिक टन दलहन व तिलहन की खरीद की गई।

किसानों को मुसीबत से उबारने के लिए उपज की खरीद के लिए बनी नेफेड को बचाना केंद्र सरकार को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परामर्श पर त्वरित प्रभाव से नेफेड की बैंक गारंटी को बढ़ाकर 42 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। यह बैंक गारंटी संप्रग सरकार के समय महज 200-250 करोड़ रुपये थी।

नेफेड में सुधार के उपायों के हैरतअंगेज नतीजे सामने आए। जो नेफेड 2011-13 के मध्य तीन फसल सीजन में कोई फसल खरीद नहीं सका था, वह अब खरीद का रिकॉर्ड बना रहा है। इसके लिए पिछली सरकार के समय समर्थन मूल्य योजना में पूर्ण क्षति की प्रतिपूर्ति के बजाय मात्र 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। नेफेड को समुचित बैंक गारंटी मुहैया कराने के परिणामस्वरूप किसानों से रिकॉर्ड खरीद संभव हो सकी। वित्तीय अनुशासन और सुधार के नतीजों को परिलक्षित करते हुए नेफेड ने अपनी कमाई से बैंकों को 220 करोड़ रुपये की नकद अदायगी की।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने इसके लिए नेफेड से किसानों की उपज की खरीद के रिकॉर्ड बनाते रहने की अपेक्षा जाहिर की। उन्होंने कहा कि नेफेड की हालत में सुधार के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि किसानों को निराश होने से बचाया जा सके। ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

माल, मांग और औद्योगिक प्राथमिकताएं

दीनदयाल उपाध्याय

आयात निर्भरता

औद्योगीकरण का अर्थ है कच्चे माल का विधायन करके उससे उपभोग योग्य वस्तुओं को तैयार करना। कच्चा माल और पक्के माल की मांग ही औद्योगीकरण के स्वरूप और मात्रा को निश्चित करते हैं। कच्चे माल के लिए व्यक्ति की दृष्टि स्वाभाविक तौर पर अपने आसपास की प्रकृति संपदा एवं कृषि उत्पादन पर जानी चाहिए। किंतु निर्मित वस्तुओं के जो स्वरूप पश्चिम में निश्चित हैं, उनसे ही बंधे रहने के कारण तथा निर्माणविधि का पूरा ज्ञान न होने के कारण हम अभी तक अपनी संपूर्ण संपत्ति का ठीकठीक उपयोग नहीं कर पाए हैं। प्रत्युत हमारा औद्योगीकरण अपने कच्चे माल का उपयोग न करके विदेशों से आयातित कच्चे अथवा अर्ध निर्मित माल के आधार पर चल रहा है। वैसे तो आज के आधुनिक उद्योगों में एकाध ही निकलेगा, जो अपने कच्चे माल की संपूर्ण आवश्यकताएं देश में पूरा कर लेता हो किंतु जो उद्योग भारत में निर्मित माल के पर्याय या पूरक के रूप में उत्पादन करने के हेतु स्थापित हुए हों, उनकी परनिर्भरता तो बहुत खलती है। प्लास्टिक और रेयन ऐसे उद्योग हैं। इनको बहुतांश में अभी तक मशीनों के लिए ही नहीं, कच्चे माल के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में यद्यपि काफी तेल पैदा किया जा सकता है, किंत साबन के लिए तेल हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है। लंबी रेशे के कपास और जूट के लिए भी देश के विभाजन के बाद हम आत्मनिर्भर नहीं रहे। हम रेडियो तो खूब बना रहे हैं किंतु उसके 90 प्रतिशत हिस्से बाहर से लाकर लगा देते हैं। ड्राइबैटरियों में 78 प्रतिशत और बिजली के बल्बों में 90 प्रतिशत आयात निर्भरता है। 1956-57 में हमें 138.73 प्रतिशत माल बाहर से मंगाना पड़ा। इसके अतिरिक्त लगभग 200 करोड़ रुपए का अर्धनिर्मित माल हम बाहर से मंगाते हैं।

हमारी इस अत्यधिक आयात निर्भरता का कारण उद्योग-धंधों में पूरी तरह विदेशी अनुकरण है। अनेक उद्योग जो विदेशी कंपनियों ने भारत में खोले हैं, वे बहुत सा कच्चा माल भी बाहर से मंगाते हैं, जैसे साबुन और रंग का उद्योग। हाल के कुछ उद्योग केवल बाहर से माल लाकर उनका पैकिंग या एकत्रीकरण मात्र यहां करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि देश के लिए तेल और खली दोनों की ही हमें नितांत आवश्यकता है, फिर भी हम उसे बराबर भारी मात्रा में बाहर भेजते जा रहे हैं। चमड़ा सिझाने के लिए अभी तक हम वाटल छाल को दक्षिण अफ्रीका से मंगा रहे हैं। यदि हम अपने पुराने उद्योगों का आधार बनाकर विकास का मार्ग निश्चित करेंगे तो फिर उल्टे बांस बरेली को भेजने वाली उक्ति चरितार्थ नहीं होगी। जिन वस्तुओं का हम सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, उनका विधायन करके हम एक प्रभावी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे हम जिन साधनों से अनेक वस्तुएं निर्माण करते आए हैं या तो उन्हें ही विकसित करेंगे अथवा उनके उपयुक्त पर्याय देश में ही ढूंढ़कर निकालेंगे। विदेशों से माल लाकर उनका थोड़ा-बहुत विधायन हमारे देश की समस्या का हल नहीं कर सकता।

खेत और कारखानों की दूरी

देश के अंदर भी कच्चे माल और उनके कारख़ानों का हमने ठीक मेल नहीं बिठाया है। बहुत से कारख़ाने विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से बंबई और कलकत्ता के आसपास खुल गए हैं। अर्थात् जहां माल है, वहां कारख़ाने खोलने के स्थान पर हमने जहां कारख़ाने हैं, वहां माल ढोने की नीति अपनाई है। इसका परिणाम एक ओर तो देश का अत्यंत ही असंतुलित औद्योगीकरण तथा दूसरी ओर बिचौलियों की बढ़ती में हुआ है। कच्चे और पक्के माल के मूल्यों के बीच तालमेल भी इस कारण नहीं बैठ पाता। हम यदि इन सभी दृष्टियों से विचार करेंगे, तो हमें औद्योगीकरण का जाल विकेंद्रीकरण के आधार पर सभी प्रदेशों एवं ग्राम-ग्राम में फैलाना होगा।

मांग

विदेशों में नए बाज़ारों की खोज

मांग और उद्योगों का जहां ठीक-ठीक संबंध हो जाता है, वहां एक संतुलित अर्थव्यवस्था रहती है। साधारणतया जिस चीज़ की मांग हो, उसे पैदा करना चाहिए, किंतु आजकल बाज़ार ढूंढ़ने, लोगों की अभिरुचि को समझने और परखने के अतिरिक्त विज्ञापन एवं प्रचारतंत्र के सहारे बाजार बनाने, लोगों की अभिरुचि निर्माण करने और बदलने पर भी बल दिया जाने लगा है। अतः हमें देश में जिन चीजों की मांग है, उनके लिए उद्योग प्रारंभ करने के साथ ही जिन चीजों को हम पैदा करते हैं उनके लिए नए-नए बाजार बनाने की भी चिंता करनी होगी। हमने पश्चिम के प्रचारतंत्र से अपनी अभिरुचि तो बदल दी और इस प्रकार अपने उद्योग-धंधों के लिए देश का बाजार समाप्तप्राय कर दिया; किंतु इस बात का प्रयास नहीं किया कि इन उद्योगों के लिए हम दूसरा बाज़ार ढूंढ़ निकालें। यदि प्रयास किया जाए तो पश्चिम के देशों में बहुत बड़ी मांग हमारी वस्तुओं के लिए उत्पन्न की जा सकती है। मनुष्य स्वभाव से कभी एक ही प्रकार की वस्तु पसंद नहीं करता। यदि आज हम मानव हस्तकौशल और दक्षता के परिणामस्वरूप कलापूर्ण, विविधता भरी, कृतियों की सुंदरता से विमुख हो मशीनों की एकरूपता की ओर

झुके हैं, तो पश्चिम में निश्चित ही इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर मशीन से मानव की कृति का प्रेम उत्पन्न होगा। हमें अपने बाज़ारों का विकास करना होगा।

देश में व्यापक बाज़ार

विदेशों में हम नए-नए बाजार खोजते और बढ़ाते रह सकते हैं, किंतु यह सत्य है कि वहां की मांग के आधार पर हम अपने देश के सुदृढ, टिकाऊ औद्योगिक ढांचे को नहीं खड़ा कर सकते। हमारे कार्यक्रम का मुख्य आधार तो हमारे देश का बाज़ार ही हो सकता है। भारत इतना विशाल देश है तथा इसकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि वह स्वयं तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को आधार बन सकता है। हमारी मांग ही कोई कम नहीं है।

मांग और उत्पादन का मेल

जब हम देश की मांग का विचार करते हैं तो हमें मनुष्य की (1) प्राथमिक और इसलिए मुख्यतः आय निरपेक्ष (income inelastic) तथा (2) बढ़ती हुई आय के साथ पैदा होने वाली मांगों का विचार करना होगा। उत्पादन की पद्धति, वित्त संचय एवं कराधान, वितरण व्यवस्था, सामाजिक विधान और रहन-सहन में परिवर्तन, इन कारणों से भी कुछ मांगों में बदल होता है। हमें इनका ध्यान रखकर ही अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। जब लोगों को रोटी और कपड़े की मांग हो उस समय हम रेडियो सेट और झूठे मोती बनाने का उद्योग प्रारंभ करें तो उचित नहीं होगा। यदि आय के बढ़ने के कारण मोटे कपड़े के स्थान पर बढ़िया कपड़े की मांग है तो हमें पैदा करना होगा। शहर-प्रधान उत्पादन प्रणाली अपनाकर हमें नगरों में लगने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना ही होगा। अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे का अभिन्न एवं अंतर्संबंध होने के कारण हमें अपनी प्रत्येक योजना का मांग पर होने वाला परिणाम दृष्टि में रखना होगा। उसकी घट-बढ़ के अनुसार ही हमें उपाय योजना करनी होगी। अतः जहां उद्योगों के स्वरूप के निर्धारण में श्रम, शक्ति, पूंजी और प्रबंध आदि को ध्यान में रखना होता है, वहां बाजार का विचार भी आवश्यक है। वास्तव में तो मांग रही तो फिर सब खेल जमाने की ज़रूरत है, यदि वह नहीं तो केवल उद्योगों के लिए ही उद्योग तो स्थापित नहीं किए जा सकते। औद्योगीकरण के कार्यक्रम की सफलता इसमें भी है कि वह किसी भी स्तर पर तथा किसी भी क्षेत्र में मांग की पूर्ति न कर सकने के कारण संकीर्णता (Bottleneck) तथा बिना मांग के उत्पादन के कारण मंदी (Depression) की स्थिति उत्पन्न न कर दे। इसके लिए हमें औद्योगिक कार्यक्रम की प्राथमिकताओं का विचार करना होगा।

मांग और उद्योगों का जहां ठीक-ठीक संबंध हो जाता है, वहां एक संतुलित अर्थव्यवस्था रहती है। साधारणतया जिस चीज़ की मांग हो, उसे पैदा करना चाहिए, किंतु आजकल बाज़ार ढूंढ़ने, लोगों की अभिरुचि को समझने और परखने के अतिरिक्त विज्ञापन एवं प्रचारतंत्र के सहारे बाजार बनाने, लोगों की अभिरुचि निर्माण करने और बदलने पर भी बल दिया जाने लगा है। अतः हमें देश में जिन चीजों की मांग है, उनके लिए उद्योग प्रारंभ करने के साथ ही जिन चीजों को हम पैदा करते हैं उनके लिए नए-नए बाजार बनाने की भी चिंता करनी होगी।

उद्योगों के प्रसार

उद्योग-धंधों को हम इन तीन वर्गों में बांट सकते हैं-(1) उपभोग वस्तु उद्योग, (2) उत्पादन वस्तु उद्योग, (3) मूल उद्योग। प्रथम श्रेणी में वे उद्योग आते हैं, जो मनुष्य के उपभोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे कपड़ा, साबुन, माचिस आदि पैदा करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे उद्योग हैं, जो उन चीज़ों को पैदा कराते हैं, जिनसे उत्पादक वस्तुएं बनती हैं। अथवा जो उनके बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूत, टायर-ट्यूब, पेंसिल का लेड, मशीनें आदि। आधारभूत उद्योग वे हैं, जिनके सहारे उपभोग या उत्पादक वस्तुएं बनती हैं। बिजली, लोहा, इस्पात, भारी रसायन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ जनोपयोगी सेवाएं रेल आदि भी इसी में शामिल हैं। यह वर्गीकरण मोटा-मोटा है। एक ही वस्तु एक स्थान पर उत्पादक वस्तु हो सकती है तो दूसरे पर उपभोग। साधारणतया विचार किया जाए तो आधारभूत उद्योग का पहला स्थान आता है, क्योंकि जब तक वे नहीं होंगे, बाक़ी उद्योग चल ही नहीं सकेंगे। उसके उपरांत उत्पादक वस्तुएं और सबसे अंत में उपभोग वस्तुएं बनाना, यही क्रम सामने आता है। किंतु जब हम मांग का विचार करते तो सबसे अधिक मांग उपभोग वस्तुओं की है। इतना ही नहीं तो वह बराबर बढ़ भी रही है। आधारभूत और उत्पादक उद्योगों में जिनको काम देते हैं, उनकी आय में वृद्धि होने के कारण उनकी मांग और बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को यदि पूरा करके योग्य उपभोग वस्तुओं का अभाव रहा तो मूल्य बढ़ जाएंगे। इसका परिणाम उत्पादक और आधारभूत उद्योगों के उत्पादन व्यय पर पड़ेगा, जो कि आगे चलकर उपभोग वस्तुएं बाज़ार में आएंगी, तब तक मूल्य स्तर, जो कि स्फीतिजनक होगा, इतना बढ़ चुका होगा कि साधारणजन के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। आधारभूत उत्पादनों का मूल्य तो उपभोग प्रकार निरपेक्ष है, किंतु उत्पादक वस्तुएं सदैव प्रचलित अभिरुचि एवं फैशन से सापेक्षिक संबंध रखती हैं। जब हम छुआछूत के कारण कांच के और चीनी के बरतनों का प्रयोग नहीं करते थे, उस समय

बड़े पैमाने पर कांच के कारखाने खोलना हितावह नहीं होता। अतः ऊपर से स्वाभाविक दिखने वाली इन प्राथमिकताओं में हमें बदल करना होगा।

उपभोग वस्तुओं को प्राथमिकता

हमने कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा कृषि पर से भार कम करने की आवश्यकता को अनुभव किया है। हमने यह भी स्वीकार किया है कि किसान हमारा प्राथमिक उत्पादक ही नहीं, वह हमारे मुख्य बाजार का क्रेता भी है। हम यदि उससे विपणनीय अतिरेक चाहते हैं, तो हमें उसकी मांग पूरी करनी होगी। इस दृष्टि से कृषि के लिए उत्पादक वस्तुएं तथा किसान की उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन हमारी प्रथम आवश्यकता है। इन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए लोगों तथा शेष के लिए भी हमें उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन करना होगा, क्योंकि संपूर्ण बाजार को हम कृषक और गैर-कृषक इस आधार पर नहीं बांट सकते। इतने व्यापक बाजार की मांग पूरा करने वाले उद्योग हमने खड़े कर दिए तो हम अधिकांश लोगों को काम दे सकेंगे। किंतु प्रश्न उपस्थित होगा कि इन उद्योगों को खड़ा करने के लिए हम उत्पादक मशीनें आदि कहां से लाएं। यदि हम कोरी स्लेट पर लिखते होते तो हमारे लिए यह बड़ी कठिनाई थी, किंतु हमारे देश में पहले से ही उपभोग-वस्तुओं का निर्माण करने वाले बहुत से उद्योग हैं। शासन अपनी विभिन्न नीतियों से उन्हें योग्य प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। कुछ अंशों तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आयात पर निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि हम उस अर्थनीति की कल्पना करके नहीं चले, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हमारा कोई संबंध न हो।

उत्पादक एवं मूल उद्योग

उद्योग उपभोग-वूस्तुओं के उद्योग के व्यापक प्रसार के साथ-साथ उत्पादक वस्तुओं के उद्योग स्वतः विकसित होते जाएंगे। आवश्यकतानुसार उन्हें संरक्षण आदि की सुविधाएं दी जा सकती हैं। हां, आधारभूत उद्योगों में से कुछ को तो हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए तथा कुछ के लिए हम एक लंबी अवधि का कार्यक्रम बनाकर चल सकते हैं। ये उद्योग पूंजी प्रधान होने के कारण एकबारगी प्रारंभ नहीं किए जा सकते। बिजली प्रथम वर्ग में आती है तथा इस्पात, भारी रसायन आदि दूसरे वर्ग में। हम यह न मान लें कि इन उद्योगों को हम अभी टालकर किसी एक ही पंचवर्षीय योजना के अंदर पूरा कर लेंगे। किसी भी एक समय इन पर एकांगी भार कठिनाई पैदा कर देगा। हां, उपभोग उद्योगों का अधिक विस्तार होने तथा देश की प्राविधिक कुशलता आदि के बढ़ाने के कारण वह सुवह्य हो सकता है। वांछित तो यह है कि चालीस वर्षों का इस संबंध में कार्यक्रम बनाकर थोड़े से प्रारंभ कर उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएं। हर समय उपभोग वस्तुओं पर बल अधिक रहे। सब लोगों को काम मिलने तथा उनकी आय के अंतर्गत ही उपभोग वस्तुओं के सुलभ होने के कारण वे अपना जीवनस्तर ऊंचा उठा सकेंगे। उनके पास जो थोड़ा-बहुत बचे उसके अधिपोषण की व्यवस्था रही तो वित्त संचय बढ़ता जाएगा। छोटे-छोटे उद्योगों में पूंजी लगाने की उन्हें स्वयं भी सुविधा रहेगी। वित्त की वृद्धि के साथ हम अधिक पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे। प्राविधिक एवं प्रबंध संबंधी योग्यता भी बढ़ती जाएगी तथा ऐसा कोई समय नहीं आएगा, जबकि उत्पादित वस्तु के लिए बाज़ार न मिलें, क्योंकि वह तो बढ़ती हुई आय और रोजगारी के साथ बढ़ेगा ही। आज हमने एक पूंजी प्रधान योजना हाथ में ली है, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर मुद्रास्फीति के मूल्य बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर कपड़े और सीमेंट का स्टाक जमा होता जा रहा है, यद्यपि लोग नंगे और आवासहीन घमते हैं।

पूंजी प्रधान भारी उद्योगों को चलाने के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर करनी पड़ती है। फल यह होता है कि पूंजी की दुर्लभता और भी बढ़ती जाती है। पूंजी और देश के अन्य साधन जब इन कुछ भारी उद्योगों के लिए ही पूरे नहीं पड़ते, तो शेष उद्योगों के सम्मुख साधनों का उत्तरोत्तर अभाव होता जाता है, जिसमें उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समाज को इस प्रकार भारी मूल्य चुकाना पड़ता है।

सुरक्षा और भारी उद्योग

भारी और आधारभूत उद्योगों का सुरक्षा की दृष्टि से अवश्य महत्त्व है। आधुनिक शस्त्रास्त्र के लिए वे अपरिहार्य हैं। किंतु किसी भी देश की सुरक्षा केवल शस्त्रास्त्रों से नहीं होती। अन्न, वस्त्र आदि की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर दुर्लक्ष्य करके सुरक्षा की तैयारी नहीं की जा सकती। इन उद्योगों को खड़ा करने में ही यदि हमने अपने साधन लगा दिए तो युद्ध के समय तो हमारी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। इसलिए सुरक्षा का विचार भी हम यथार्थवादी एवं सर्वतोमुखी दृष्टिकोण से करें।

भारी उद्योगों के लिए भारी बलिदान

सुरक्षा के समान ही कई बार प्रतिष्ठा की भावना से भी भारी उद्योगों का कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि भारी उत्पादक और आधारभूत वस्तुओं की उत्पादन क्षमता हमें विश्व की आंखों में ऊंचा उठा देगी। किंतु ये सब कारण अर्थशास्त्र की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इन्हें पूरा करने के लिए न केवल हमें अधिक दिनों तक अपने जीवनस्तर को नीचा रखना पड़ेगा, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रजातंत्र के सिद्धांतों की बलि देनी होगी। इस कार्यक्रम की सफलता केवल सोवियत मूल्यों की स्थापना और वहां जैसे नेतृत्व के प्रादुर्भाव और मान्यता पर ही नहीं अपितु उत्पादन और उपभोग और व्यापक नियंत्रण के सफल व्यवहार की संभावनाओं पर निर्भर करती है। जब तक यह नहीं होता और जब तक निजी क्षेत्र में उत्पादन की छूट तथा उपभोग स्वतंत्रता विद्यमान है, तब तक पूंजी प्रधान उत्पादन के क्षेत्र में भारी वृद्धि का परिणाम मुद्रास्फीति और अंत में संपूर्ण योजना का विस्फोट ही होगा। ■

('भारतीय अर्थ-नीति विकास की एक दिशा' से साभार)

भाजपा सांसद रामचंद्र बैंदा नहीं रहे

(7 फरवरी 1946 – 12 जून 2018)

फरीदाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता 71 वर्षीय श्री रामचंद्र बैंदा का 12 जून को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में देहांत हो गया। श्री बैंदा के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर शोक व्यक्त करने उनके घर गए। श्री खट्टर ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचन्द्र बैंदा का निधन हरियाणा में भाजपा के लिये एक बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें व उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें। श्री खट्टर ने श्री बैंदा को एक अनुभवी राजनेता बताया, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि श्री बैंदा पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। श्री खट्टर ने यह भी कहा कि बैंदा बहुत ही हंसमुख इंसान थे। श्री बैंदा के निधन पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल आदि ने भी शोक व्यक्त किया।

पूर्व सासंद श्री रामचंद्र बैंदा हिसार जिले के खाबड़ा कलां गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 7 फरवरी 1946 को हुआ था। श्री रामचंद्र बैंदा 1980 में भाजपा में राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। उन्होंने 1996 में भाजपा की टिकट पर फरीदाबाद से लोकसभा

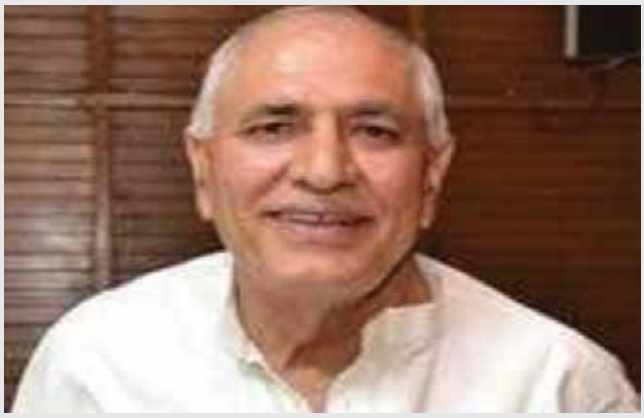

सीट जीती। 1996 से 1998 तक वे डिफेंस कमेटी के सदस्य रहे। 1998 में 12वीं लोकसभा में वे दूसरी बार सांसद बने। 1998-99 में वे कृषि समिति के सदस्य बने। श्री बैंदा 1999 में 13वीं लोकसभा में तीसरी बार सांसद बने। 1999-2000 के दौरान वे कई कमिटियों के सदस्य रहे। गौरतलब है कि श्री बैंदा 1964 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने और आर्य समाज एवं सामाजिक संस्थाओं में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। ■

भाजपा के चिकमंगलूर (कर्नाटक) महासचिव मोहम्मद अनवर की हत्या

कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और भाजपा नेताओं की हत्या का सिलसिला अब भी जारी है। चिकमंगलूर में 22 जून की रात बाइक पर आए अपराधियों ने भाजपा नेता मोहम्मद अनवर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। श्री अनवर चिकमंगलूर में पार्टी के महासचिव थे। वे रात 9.30 बजे के आसपास एक स्थानीय कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान कुछ बाइक सवार अपराधियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद श्री मोहम्मद अनवर को चिकमंगलूर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक राजनीतिक हत्या है और इस हत्या के पीछे स्थानीय कट्टरपंथियों का हाथ है। करंदलाजे ने टवीट् कर कहा कि चिकमंगलूर भाजपा महासचिव अनवर की बाइक सवार कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। उन्हें पहले भी जान से मारे जाने की धमकियां दी जा रही थीं और अति निंदनीय घटना है। आखिर, कनार्टक किस दिशा की तरफ जा रहा है। उन्होंने चिकमंगलूर के पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यह बड़े दुःख की बात है कि कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की अनेक हत्याएं हुई हैं और यह घृणित सिलसिला अब भी जारी है। ■

क्या कांग्रेस विचारधाराविहीन है? क्या मोदी का विरोध ही मात्र विचारधारा है

अरुण जेटली

कुछ हफ्ते पहले यूपीए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि पकौड़े तलना कोई रोजगार सृजन नहीं है। अपने बाकी संगी साथियों में चतुर होते हुए, वह (चिदंबरम) शायद मुद्रा योजना की सफलता को कमतर आंकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत समाज के कमजोर तबकों को 12.90 करोड़ कर्ज दिए गए हैं। मुद्रा योजना स्पष्ट रूप से लाखों हाथों के लिए नए काम पैदा कर रहा है और साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहा है।

दो दिन पहले, राहुल गांधी अपने ओबीसी समर्थकों को सम्बोधित करते हुए मोदी की नीतियों पर प्रहार के लिए अमेरिका के सफल उद्योगपतियों का हवाला दिया था। उन्होंने कोका-कोला के संस्थापक को 'शिकंजी बेचने वाला' व मैक्डोनाल्डस के संस्थापक को 'ढाबेवाला' बताया था। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वह तथ्यात्मक रूप से गलत था, लेकिन बड़ा बिंदु यही है कि उन्होंने उन कामों में ऐसे गुण देखे जो अनेक स्टार्टअप शुरू करने का आधार बन सकते हैं। 'भारत एक खोज' जैसी महान् रचना के लेखक (जवाहरलाल नेहरू) के ये पड़नाती अपनी 'त्रुटियों' की इसी प्रथा पर चलते हुए इस देश को 'कोका कोला की पुनः खोज' शीर्षक एक महान् कृति दे सकते हैं।

यह प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार ही है, जिसने वर्ष 2015 में इस तरह के स्वरोजगार के अवसरों के महत्व को महसूस किया उसके लिए मुद्रा योजना शुरू की गई। अधिकांश लाभार्थियों ने छोटे ऋण ले लिए, छोटे उद्यम स्थापित किए और खुद को, और शायद एक या दो लोगों को रोजगार दिया। यूपीए ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं दोहराता हूं कि यह यूपीए ही थी, जिसने 2008-2014 के दौरान संप्रग सरकार ने बैंकों के जरिए 15 बड़े कर्ज चूककर्ता कर्जदारों को बिना सोचे विचारे पैसा दिया। राहुल गांधी गोएबल्स का तरीका अपनाते हुए 'तथ्य से विपरीत बातें कर रहे हैं।' लोगों के सामने उन्होंने जो दावा किया वह ठीक है जिसे हमने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

कांग्रेसियों का मानना है कि 2.5 लाख करोड़ बैंक ऋण माफ कर दिए गए हैं? क्या यह समझने में असमर्थता के कारण है कि देनदार द्वारा निष्पादित संपत्ति की सेवा नहीं की जाती है, नब्बे दिनों के बाद यह गैर निष्पादित संपत्ति बन जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वसूली की संभावना में गिरावट आई है। कॉलम में एक बदलाव होता है और बैंक को इस आधार पर प्रावधान करना पड़ता है कि वसूली की संभावना कम हो जाती है, लेकिन देनदार देयता बनी हुई है। कोई छूट नहीं है। जब या तो आईबीसी के माध्यम से या कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण वापस वसूल किया जाता है, तो प्रविष्टि उलट जाती है। 'एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए बैंक परिचालन की प्राथमिक प्रक्रिया की समझ नहीं होना पूरी पार्टी ही नहीं देश के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वंशवाद आधारित राजनीतिक दलों में राजनीतिक पद वंशानुगत होते हैं। दुर्भाग्य से बुद्धिमानी वंशानुगत नहीं होती है। यह सीखकर हासिल की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह अचानक प्यार क्यों?

1990 के शुरुआत में ओबीसी ने कांग्रेस

वंशवाद आधारित राजनीतिक दलों में 'व्यक्ति व परिवार' विशेष की चलती है और विचारधारा को कोई नहीं पूछता। अपनी सुविधा अनुसार चीजें तय करके कभी आप ओबीसी का विरोध करते हैं, कभी पकौड़ा तलने का मजाक उड़ाते है, कभी इन्हीं लोगों के लिए घरियाली आंसू भी बहाते हैं, कभी ढाबा चलाना आपको उपयोगी दिखने लगता है। यह केवल उन दलों के साथ होता है जो विचारधाराविहीन हो और जो अपने आपको सीमांत में संकुचित रखती है, या फिर क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बनने के लिए तैयार हो।

पार्टी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है, स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में मंडल आयोग के खिलाफ आक्रामक भाषण दिया था। हाल ही में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का भी विरोध किया, उन्होंने संसद में संवैधानिक संशोधन के खिलाफ मतदान किया। कांग्रस हमेशा अवसर देख कर आरक्षण का समर्थन करती है। यह स्पष्ट रूप से ओबीसी के लिए कोटा को कम करना चाहती है, यह जानते हुए कि न्यायपालिका आरक्षण पर 50 प्रतिशत से अधिक छूट की अनुमति नहीं देगी, नए दावेदार ओबीसी कोटा में खा जाएंगे।

राहुल के कुछ और कमाल

कुछ हफ्ते पहले सिंगापुर में अपने साक्षात्कारकर्ता के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने दर्शकों को यह कहकर भौंचक्का कर दिया कि भारत में एमआरआई मशीनें जोड़ने से चिकित्सा में क्रांति होगी। कैसे? सिवाय अन्य अस्पतालों के साथ अपना विवरण साझा करके एक रोगी की गोपनीयता का उल्लंघन करने के अलावा और क्या हासिल होगा?

राहुल गांधी कर्नाटक की एक सभा लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा की उनकी पार्टी का मानना है कि सिंगापुर में केवल एक जीएसटी दर है, जबकि सिंगापुर सभी खाद्य पदार्थों, सस्ते कपड़ों और जूते, चिकित्सा और शिक्षा पर 7% जीएसटी चार्ज करता है, विलासिता वस्तुओं- बीएमडब्ल्यू कार, अल्कोहल और पांच सितारा होटल के रूप में खर्च करता है। भारत ने अधिकांश खाद्य पदार्थों को छूट दी है। क्या हमारे पास खाद्य वस्तुओं, हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू कारों के लिए समान दर होनी चाहिए? सिंगापुर में भारत के विपरीत, कोई बीपीएल या कम आय वाले समूह नहीं हैं।

शिक्षा पर उनका मानना है कि हमारे पास 200 आईआईटी होना चाहिए। क्या यूपीए ने ऐसा कभी किया? नहीं। यह एनडीए की सरकार है, जो अब पूरे देश में आईआईटी, आईआईएम और एम्स का गठन कर रही है, उपरोक्त सभी बयानों में, कोई विचारधारा नहीं है। सारे बयान अज्ञानता या जान बूझकर मोदी विरोध के कारण दिए गए है।

वंशवाद आधारित राजनीतिक दलों में 'व्यक्ति व परिवार' विशेष की चलती है और विचारधारा को कोई नहीं पूछता। अपनी सुविधा अनुसार चीजें तय करके कभी आप ओबीसी का विरोध करते है कभी पकौड़ा तलने का मजाक उड़ाते है, कभी इन्हीं लोगों के लिए घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, कभी ढाबा चलाना आपको उपयोगी दिखने लगता है। यह केवल उन दलों के साथ होता है, जो विचारधाराविहीन हो और जो अपने आपको सीमांत में संकुचित रखती है, या फिर क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बनने के लिए तैयार हो। इनका सबसे बड़ा लक्ष्य नरेन्द्र मोदी का विरोध है। ■

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं)

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी।

एनईसी राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।

एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को करेगी। परिषद समय-समय पर परियोजना में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी। परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त होंगी।

एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। 2002 के संशोधन के बाद एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और एनईसी इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाएगी। ■

सीधी भर्ती प्रक्रिया: एक जरूरी निर्णय

भूपेंद्र यादव

केंद्र सरकार द्वारा 'सीधी भर्ती' के माध्यम से लोक सेवाओं में 'संयुक्त सचिव' स्तर के अधिकारियों को रखे जाने का निर्णय चर्चा में है। दरअसल, सरकार ने हाल ही में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत आवेदनकर्ता सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं होने के बावजूद सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में देश निर्माण के कार्यों में अपना योगदान दे सकेंगे।

केंद्र सरकार के इस निर्णय पर सहमति-असहमति के बीच कुछ तथ्यात्मक विषय उभरे हैं, जिस कारण इस निर्णय को समझना समीचीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह के निर्णय पहली बार लिये गये हैं अथवा ऐसा पहली बार होने जा रहा है।

अगर पीछे देखें, तो अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें सीधी भर्ती से विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दे चुके हैं। उदाहरण के तौर पर विमल जालान, मोंटेक सिंह अहलुवालिया और शंकर आचार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं सीधी भर्ती के माध्यम से देते रहे हैं। अतः इस निर्णय को पहली बार उठाया गया कदम कह कर प्रश्नचिह्न खड़ा करना उचित नहीं है।

इस कदम को राजनीतिक चश्मे से देखना भी ठीक नहीं। सही मायने में देखा जाये, तो यह कार्मिक मंत्रालय द्वारा काफी सोच, विचार और मंथन के बाद लिया गया निर्णय है, जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि देश की नौकरशाही और संघ लोक सेवा आयोग से आनेवाले अधिकारियों में योग्यता का अभाव है अथवा कोई कमी है।

यह निर्विवादित है कि भारत के पास एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है और हमारी नौकरशाही व्यवस्था अत्यंत ही योग्य है। सीधी भर्ती का यह फैसला व्यावहारिकता की कसौटी पर वर्तमान की जरूरत को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का देशहित में कैसे उपयोग हो, के संबंध में एक ठोस और निर्णायक समाधान मात्र है।

सीधी भर्ती की इस प्रक्रिया को संसद की 'कमेटी ऑन इस्टीमेट 2016-17' की लोकसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के माध्यम से समझने पर स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आयेगी।

यह निर्विवादित है कि भारत के पास एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है और हमारी नौकरशाही व्यवस्था अत्यंत ही योग्य है। सीधी भर्ती का यह फैसला व्यावहारिकता की कसौटी पर वर्तमान की जरूरत को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का देशहित में कैसे उपयोग हो, के संबंध में एक ठोस और निर्णायक समाधान मात्र है।

सदन में पेश इस रिपोर्ट में समिति ने न्यूनतम सीधी भर्ती की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे न केवल सरकारी कार्यशैली में बदलाव आयेगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों के सुझावों व विचारों को भी सरकारी प्रणाली का हिस्सा बनाया जा सकेगा। समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अधिकारी अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

इस वजह से तकनीकी पहलुओं पर कुछ मामलों में वे योग्य होने के बावजूद अनभिज्ञ होते हैं। लिहाजा नीति नियामक तैयार करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीधी भर्ती से इस आवश्यकता की तर्कसंगत पूर्ति की जा सकती है तथा विशेषज्ञों की क्षमता का लाभ लिया जा सकता है।

हालांकि, कुछ लोग इस प्रश्न पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इससे कहीं उन लोगों में उत्साहहीनता का भाव न पैदा हो जाये, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से चयनित होकर लोक सेवा में आते हैं।

ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि व्यावहारिकता की कसौटी पर इससे प्रतियोगी परीक्षाओं से आनेवाले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों के दक्ष लोगों को उच्च स्तरीय सेवा में लाने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि संयुक्त सचिव स्तर तक पहुंचने में एक अधिकारी को लंबा समय खर्च करना पड़ता है। इस दौरान वह दस साल से ज्यादा जिले और तहसील स्तर पर कार्य करते हुए जमीनी स्थिति का सटीक अनुभव प्राप्त करते हैं।

लोक सेवा में लंबा प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के बाद ही कोई अधिकारी इस

स्थिति में होता है कि उसे नीति निर्माण का दायित्व दिया जाये। अतः यदि सीधी भर्ती से अनुभवी लोगों को लाया जाता है, तो इससे प्रतिस्पर्धा के साथ सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। बहुमुखी विकास के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ कार्य करें और यह पूर्ण सहभागिता से ही संभव है।

निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की योग्यता व क्षमता का लाभ सरकारी सेवाओं में लिया जाये और सरकारी सेवाओं के योग्य एवं अनुभवी व क्षमतावान लोगों के विवेक का लाभ निजी क्षेत्रों में देने का प्रावधान तैयार हो। परस्पर सहयोग की यह भावना जब सरलता और सुगमतापूर्वक व्यवहार में आयेगी, तो देश के विकास को और गति मिलेगी। संसद की समिति ने ऐसे प्रावधानों की जरूरत को भी महसूस किया है।

सीधी भर्ती के मुद्दे पर कांग्रेस समेत कुछ दलों का यह कहना कि यह कोई प्रभावी फैसला अथवा 'गेम-चेंजर' नहीं है, गलत है। चूंकि, मेरा खुद का संसदीय स्थायी समितियों का कार्यानुभव बताता है कि केंद्र सरकार के नीति निर्धारण व उसे लागू कराने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले संयुक्त सचिव स्तर पर ही तय होते हैं। ऐसे में जाहिर है कि इससे कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आयेगा और नवाचार के द्वार खुलेंगे। आखिर खुली हवा में सांस लेने के लिए हमें भी तो अपनी बंद खिड़कियां खोलनी होंगी।

जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश में कोई भी निर्णय सरकार ले, उसे राजनीतिक बहस में लाने और राजनीति करने से विपक्ष बाज नहीं आता। सीधी भर्ती का विषय भी विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे से अछूता नहीं है। कांग्रेस ने सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का ऐसा करना सिवाय राजनीतिक कवायद के, और कुछ भी नहीं है।

केंद्र सरकार आरक्षण की नीति को लेकर स्पष्ट है और वह संविधान सम्मत ढंग से लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता अनेक बार जाहिर कर चुकी है। लिहाजा, इस नीतिगत फैसले पर विपक्ष का यह शिगूफा केवल राजनीतिक अवरोध की भावना से उठाया गया कदम है।

आज जब हम प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनिया के समृद्ध देशों के साथ कंधे-से-कंधा मिला कर चलने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसे में हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करने की जरूरत है। सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवाओं एवं नीतिगत स्तर के निर्णयों में संबंधित क्षेत्रों की योग्यताओं की क्षमता का उपयोग करके ही हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य कर सकेंगे। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांझा किया अपना फिटनेस वीडियो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी श्री विराट कोहली द्वारा दी गई फिटनेस चुनौती को स्वीकार करते हुए 13 जून को अपना फिटनेस वीडियो सांझा किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, 'यह मेरे प्रातःकालीन अभ्यासों में से कुछ पल हैं। योग के साथ साथ मैं पंचतंत्र अथवा प्रकृति के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से प्रेरित मार्ग पर भ्रमण करता हूं। यह बेहद स्फूर्तिदायक और ऊर्जावान है। मैं श्वास व्यायाम का अभ्यास भी करता हूं #HumFitToIndiaFit।

मैं प्रत्येक भारतीय से हर दिन का कुछ हिस्सा फिटनेस के लिए समर्पित करने की अपील करता हूं। जिस भी व्यायाम में आप को सुविधा हो, उसका अभ्यास करें। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। #FitnessChallenge#HumFitToIndiaFit

फिटनेस चुनौती को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी, टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री मनिका बत्रा और सभी आईपीएस अधिकारियों विशेष रूप से चालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग को नामांकित किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 'मैं निम्नलिखित को फिटनेस चुनौती के लिए नामांकित करते हुए खुश हूं:

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी, भारतीय गौरव और वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली मनिका बत्रा। आईपीएस वर्ग के सभी बहादुर अधिकारीगण विशेष रूप से चालीस वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी।' ■

डॉ. मुखर्जी का बलिदान दिवस

बंगाल-कश्मीर के लिए ऋणी हैं हम

कैलाश विजयवर्गीय

23 जून देश के महान् सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉ. मुखर्जी को हम याद करते हैं 'एक देश, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान' के संकल्पों को पूरा करने के लिए, कश्मीर में बलिदान देने के लिए। हम उन्हें याद करते हैं पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए, उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शिता के लिए। हम उन्हें याद करते हैं आजादी के बाद देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए। हम उन्हें याद करते हैं कांग्रेस की तमाम गलतियों का विरोध करने के लिए, उनके दृढ़ सकल्पों के लिए। डॉ. मुखर्जी का हम स्मरण करते हैं कि देश की स्वतंत्रता से पहले और बाद में किए गए उनके कार्यों के लिए। देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के लिए उनके कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

डॉ. मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम देश में जलते हुए दो राज्यों पश्चिम बंगाल और कश्मीर के हालातों पर गौर करें। इन दोनों राज्यों को भारत में बनाये रखने के लिए डॉ. मुखर्जी का सबसे ज्यादा योगदान है।

डॉ. मुखर्जी 1937 में बंगाल की राजनीति में शामिल हुए। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बंगाल हुए चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का अच्छी संख्या में सीटें मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस को साथ लेकर फजलुल हक और मुस्लिम लीग में समझौता करा दिया था। इस समझौते में कांग्रेसी नेता नलिनी रंजन सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें अंग्रेज गर्वनर का नजदीकी माना जाता था। उस समय कांग्रेस के कारण ही बंगाल में मुस्लिम लीग का सरकार बनी थी। मुस्लिम लीग सरकार ने तुष्टीकरण और साम्प्रदायिकता के आधार पर गंदी राजनीति करते हुए हिन्दुओं की भागीदारी को कम करने की कोशिश की थी। उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की चुप्पी साधने के बावजूद मुस्लिम लीग सरकार की नीतियों का विरोध किया। खासतौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। डॉ. मुखर्जी की राजनीतिक कुशलता के कारण ही 1941 में बंगाल को मुस्लिम लीग सरकार से मुक्ति मिली और फजलुल हक के साथ गठबंधन में नई सरकार बनी। श्यामा-हक सरकार में डॉ. मुखर्जी ने वित मंत्रालय संभाला था। डॉ. मुखर्जी ने अंग्रेज सरकार और मुस्लिम लीग की तमाम कोशिशों को धता बताते हुए सम्पूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोका था। डॉ. मुखर्जी न होते तो पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का डॉ. मुखर्जी ने 1937 में विरोध किया था, उसी तरह के हालात पश्चिम बंगाल का कई वर्षों से झेल रहा है। पहले कांग्रेस, फिर वामदलों और अब तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति के खिलाफ अभियान चला रखा है। वोटों के लालच में बंगलादेशियों को लाकर गांवों में बसाया जा रहा है। सरकारी संरक्षण में चल रहे अभियान के कारण तमाम गांवों से हिन्दुओं का भागना पड़ रहा है। उनकी बहू-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की धमकी देकर उन्हें घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी हिन्दुओं के साथ उसी तरह की नीति अपना रही है जैसे कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने डोगरों के साथ किया था।

डॉ. मुखर्जी हमेशा मानते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। आज कश्मीर में जो भी खून-खराबा हो

डॉ. मुखर्जी हमेशा मानते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। आज कश्मीर में जो भी खून-खराबा हो रहा है उस सबके लिए केवल कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। डॉ. मुखर्जी ने ही यह नारा दिया था कि "एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा- नही चलेगा"। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि जम्मू-कश्मीर की सीमा में भारत सरकार के परमिट बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। डॉ. मुखर्जी ने इस परमिट का विरोध किया था।

रहा है उस सबके लिए केवल कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। डॉ. मुखर्जी ने ही यह नारा दिया था कि "एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा- नही चलेगा"। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि जम्मू-कश्मीर की सीमा में भारत सरकार के परमिट बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। डॉ. मुखर्जी ने इस परमिट का विरोध किया था। वे कहते थे कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि जम्मू-कश्मीर का भारत सौ प्रतिशत विलय हो चुका है और दूसरी परमिट का प्रावधान किया गया है। इसे माना नहीं जा सकता है। देश के किसी नागरिक को जम्मू-कश्मीर में जाने से नहीं रोका जा सकता है। जिस तरह की नीति मुस्लिम लीग ने बंगाल में 1937 से लेकर 1941 के बीच हिन्दुओं के खिलाफ अपनाई उसी तरह की नीति शेख अब्दुल्ला सरकार ने डोगराओं के खिलाफ अपनानी शुरू कर दी थी। शेख अब्दुल्ला सरकार की हिन्दू विरोधी नीतियों के खिलाफ 1952 में डोगरा समाज के बड़े नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने बलराज मधोक के साथ जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद पार्टी बनाई थी। इस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को भारत में जोड़े रखने के लिए बड़ा कार्य किया था। शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश में थे। उसी तरह के बयान आज कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीन साल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ राज्य को अच्छा प्रशासन देने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए सरकार बनाई थी। महबूबा सरकार आतंकवाद पर काबू करने में बेअसर रही। डॉ. मुखर्जी के बलिदान के कारण ही पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर पाया और न ही कभी कर पायेगा। डॉ. मुखर्जी 8 मई 1953 को दिल्ली से ट्रेन में कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ थे। डॉ. मुखर्जी का रास्ते में जगह-जगह स्वागत किया गया। 10 मई को जम्मू सीमा में घुसने पर डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमयी हालातों में उनका निधन हो गया। डॉ. मुखर्जी की दूरदर्शिता को देखते हुए उस समय अगर धारा 370 को समाप्त कर दिया जाता तो आज कश्मीर के हालात इतने खराब न होते। आज पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर दोनों राज्य जल रहे हैं। जनता परेशान है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही दोनों राज्यों की जनता की शांति उम्मीद जल्दी पूरी हो। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून को आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। भिलाई इस्पात सयंत्र के आधुनिकीकरण में उत्पादन, उत्पाद, गुणवत्ता, लागत, प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस परिवर्तित आधुनिक प्लांट के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। ये देख के बहुत कम लोगों को पता होगा कि कच्छ से कटक तक और करगिल से कन्याकुमारी तक आजादी के बाद जो भी रेल की पटरियां बिछी हैं। उनमें अधिकतर इसी धरती से आप ही के पसीने के प्रसाद के रूप में पहुंची हैं। निश्चित तौर पर भिलाई ने सिर्फ स्टील ही नहीं बनाया है, बल्कि भिलाई ने जिंदगियों को भी संवारा है। समाज को सजाया है और देश को भी बनाया है।

श्री मोदी ने कहा कि भिलाई का ये आधुनिक परिवर्तित स्टील प्लांट अब न्यू इंडिया की बुनियाद को भी स्टील जैसा मजबूत करने का काम करेगा। भिलाई और दुर्ग में तो आपने खुद अनुभव किया है कि कैसे स्टील प्लांट लगाने के बाद यहां की तस्वीर ही बदल गई है। इस वातावरण को देखकर मुझे विश्वास है कि बस्तर के नगर में जो स्टील प्लांट जो स्थापित हुआ है। वो भी बस्तर अंचल के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति देने में यहां के स्टील अयस्क, लौह अयस्क ये खनन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर आपका और विशेषकर मेरे आदिवासी भाईयो-बहनों का अधिकार है। यही वजह है कि हमनें सरकार में आने के बाद एक बहुत बड़ा कानून में बदलाव किया है और हमें ये सुनिश्चित किया कि जो भी खनिज निकलेगा, उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा वहां के स्थानीय निवासियों को उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ये हमनें कानूनन तय कर लिया है और इसलिए खनन वाले हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई। ■

असम : 19 कैंसर अस्पतालों का शिलान्यास

आजादी के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा कदमः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 जून को प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री रतन टाटा के साथ असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में गुवाहाटी में एक साथ 19 कैंसर अस्पतालों का शिलान्यास किया और इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम की भाजपा-नीत सर्बानंद सोनोवाल सरकार की राज्य के गरीबों के उत्थान एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के जीवन का कल्याण ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की प्राथमिकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज असम में एक साथ कैंसर की तीनों कैटेगरी लेवल I, लेवल II और लेवल III में 19 कैंसर अस्पतालों का भूमि-पूजन हुआ है, यह मेरे लिए आनंद का विषय है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद असम की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का इससे बड़ा कदम कभी नहीं उठाया गया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमेन एवं प्रसिद्द उद्योगपति श्री रतन टाटा को हृदय से धन्यवाद करते हुए कहा कि आजादी के पहले से लेकर आज तक, देश की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने में टाटा ट्रस्ट हमेशा से आगे रहा है और देश को सर्वप्रथम मानते हुए उसने अपनी महती भूमिका अदा की है।

श्री शाह ने कहा कि असम में पिछले दो वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि इससे पहले 15 वर्षों तक यहां कांग्रेस की सरकार रही, नॉर्थ-ईस्ट में भी ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रही। उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त असम सहित पूरा नॉर्थ-ईस्ट हिंदुस्तान की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के कुशासन और विकास के प्रति उदासीनता के कारण देश की जीडीपी में नॉर्थ-ईस्ट का योगदान लगातार गिरता चला गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज फिर से एक ऐसा समय आया है जब असम सहित पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में भाजपा सरकारों के कारण विकास की बयार चलनी शुरू हुई है जिससे नॉर्थ-ईस्ट फिर से देश की जीडीपी में अपने योगदान को गति प्रदान करने लगा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि असम में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राज्य की जनता ने विकास के लिए भाजपा को चुना तो देश और दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि उत्तर-पूर्व के दुर्गम इलाकों का विकास कैसे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में दो ही वर्षों में राज्य और देश की जनता में विश्वास का संचार हुआ कि असम भी एक विकसित राज्य बन सकता है और देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

श्री शाह ने कहा कि पिछले दो सालों में असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक डेवलपमेंट का काम कर दिखाया है चाहे वह कनेक्टिविटी की बात हो या फिर बुनियादी सुविधाओं राज्य के गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की बात। उन्होंने कहा कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि रेल, रोड और आईटी कनेक्टिविटी को दुरुस्त किये बगैर विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता कनेक्टिविटी ही रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेल, रोड और आईटी कनेक्टिविटी, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था, औद्योगिक विकास और शिक्षा सुधार के विजन के साथ उत्तर-पूर्व में विकास की परिकल्पना को राज्य की भाजपा सरकारें निरंतर साकार करने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि असम में इन्वेस्टमेंट समिट से भी विकास योजनाओं को मूर्त्त रूप देने में काफी कामयाबी मिली है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से समग्र देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए 2017 में एक सुनियोजित आरोग्य नीति तैयार की गई और देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए उच्चतम स्तर की हेल्थ फैसिलिटी का एक चक्र तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के गरीबों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निजात दिलाने के लिए आयुष्मान भारत की योजना लेकर आये, जिसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख

रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही जेनरिक दवाइयों के 6000 से अधिक स्टोर्स जन-साधारण को 400 से अधिक जीवन रक्षक दवाइयां 20% से 60% कम मूल्य में उपलब्ध करायी जा रही है।

असम में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 19 कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखे जाने पर श्री शाह ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा को हृदय से बधाई देते हुए कहा कि पहले असम से लगभग 30 हजार और पूरे नॉर्थ-ईस्ट से लगभग 60 हजार कैंसर से ग्रस्त पीड़ितों को इलाज के लिए प्रतिवर्ष दिल्ली या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब जबकि कैंसर से लड़ने के लिए थ्री लेयर सिस्टम असम में ही डेवलप हो रहा है तो यह न केवल असम बल्कि नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्य के लोगों के लिए यह जीवनदायिनी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष फरवरी में ही ये योजना तैयार की गई, आज भूमिपूजन भी संपन्न हो रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 19 कैंसर अस्पताल निस्संदेह राज्य के लोगों में कैंसर से लड़ने और उसे परास्त करने के जज्बे को विकसित करेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा और श्री रतन टाटा से आग्रह करते हुए कहा कि यदि इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कम-से-कम केंसर के लेवल I और लेवल II के एक-एक भी सेंटर बन जाएं और इसे लेवल I के अन्य सेंटरों से कनेक्ट कर दिया जाय, तो यह पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हो सकेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिशन इन्द्रधनुष के जरिये दो साल में ही 18 करोड़ से अधिक तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें कई प्रकार के रोगों से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण का काम सालों पूर्व ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे अनदेखा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।

मोदी सरकार द्वारा असम के विकास के लिए उठाये गए क़दमों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि 13वें वित्त आयोग में जहां कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने असम को विकास के लिए महज 79,000 करोड़ रुपये ही दिए थे, वहीं 14वें वित्त आयोग में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने असम के विकास के लिए 1,45,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके साथ-साथ असम को क्रूड ऑयल की रॉयल्टी के तौर पर 8,000 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को लगभग 24,000 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि असम को कैम्पा फंड के तहत लगभग 100 करोड़, स्मार्ट सिटी के तहत 191 करोड़, स्वच्छ भारत योजना के लिए 33 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 99 कोर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना में 400 करोड़, अटल मिशन में 591 करोड़ और नेशनल हाईवे के लिए 15,000 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत से डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर रोड कम रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, आईटी कनेक्टिविटी भी बेहतर की जा रही है और बांग्लादेश तक रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी के जरिये पूर्वोत्तर को विकास की मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तय किया है कि हर 15 दिनों में कोई न कोई एक केन्द्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के किसी-न-किसी राज्य में मौजूद रहेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास को दिल्ली से नॉर्थ-ईस्ट लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की विजनरी

पहले असम से लगभग 30 हजार और पूरे नॉर्थ-ईस्ट से लगभग 60 हजार कैंसर से ग्रस्त पीड़ितों को इलाज के लिए प्रतिवर्ष दिल्ली या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब जबकि कैंसर से लड़ने के लिए थ्री लेयर सिस्टम असम में ही डेवलप हो रहा है तो यह न केवल असम बल्कि नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्य के लोगों के लिए यह जीवनदायिनी सिद्ध होगा।

गवर्नमेंट ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि नॉर्थ-ईस्ट हिंदुस्तान के लिए अष्टलक्ष्मी का रूप है और निश्चित रूप से ये देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभायेंगे।

श्री शाह ने असम की जनता और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से श्री रतन टाटा को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा कि टाटा ट्रस्ट ने राज्य के गरीब लोगों के लिए काफी सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम असम में 15 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो साल में कर दिखाया है। ■

खराब सुरक्षा स्थिति को लेकर भाजपा ने समर्थन वापस लिया

भारतीय जनता पार्टी ने 19 जून को जम्मू-कश्मीर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस घोषणा के बाद राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा को इस्तीफा सौंप दिया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव ने कहा कि तीन साल पहले जो जनादेश आया था तब ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण यह गठबंधन हुआ था, लेकिन जो परिस्थितियां बनती जा रही थीं, उससे गठबंधन में आगे चलना मुश्किल हो गया था।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव द्वारा ने 19 जून को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के शुरुआत में राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था। पिछले तीन सालों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गठबंधन सरकार के उद्देश्यों - राज्य के तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में शांति, विकास और प्रगति के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की।

श्री माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सभी मामलों में जम्मू-कश्मीर की हमारी गठबंधन सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपये का एक विशाल विकास पैकेज घोषित किया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही दिया जा चुका है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सही बनाए रखने के लिए जब भी जरूरत पड़ी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय ने पूरी सक्रियता के साथ राज्य मशीनरी की सहायता की।

राज्य के शोषित और पीड़ित वर्ग हेतु सुखद समाधान खोजने के दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लाने के उद्देश्य से पूर्व डीआईबी को वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया।

इन सभी उपायों के बावजूद हमने पाया कि राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर के मूल मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रभावी नहीं रही है। सुरक्षा परिदृश्य के बिगड़ने से जीवन के बुनियादी मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी आदि की रक्षा के बारे में गंभीर चिंता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। दिन-दहाड़े श्रीनगर शहर के दिल में शुजात बुखारी जैसे सम्मानित संपादक की हत्या राज्य की स्थिति के बिगड़ने और कट्टरता के बढ़ने का द्योतक है।

हालांकि सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ सालों में स्थिति को काबू करने की दिशा में शानदार काम किया है, लेकिन क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी (जो राज्य सरकार की होती है) में गंभीर कमियां देखने को मिली। घाटी की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी ने माहौल में सुधार लाने में काफी कम रुचि दिखाई।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जम्मू-कश्मीर महान राष्ट्रीय महत्व का विषय भी है। राज्य में खराब सुरक्षा स्थिति को लेकर देश में गंभीर चिंता का माहौल है। भाजपा के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि है और इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

दूसरी तरफ, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में उचित विकास और प्रगति की कमी के कारण नाराजगी और भेदभाव की भावना घर कर रही थी। सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जम्मू और लद्दाख के क्षेत्रों सहित पूरे राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। फिर भी, उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां सरकार समग्र रूप से कम उत्तरदायी और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति भावशून्य दिखाई पड़ी।

श्री माधव ने कहा कि इस तरह के परिदृश्य में, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बने रहने में अपने आप को असमर्थ पाया और इसलिए राज्य में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लिया। ■

प्रधानमंत्री द्वारा नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून को छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने नया रायपुर स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री को कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप पुरी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी उपस्थित थे। नया रायपुर का एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र देश का 10वां स्मार्ट सिटी केंद्र बन गया है। महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 9 नगरों में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र परिचालन में है। ये नगर हैं- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापत्तनम, भोपाल और काकीनाडा।

प्रधानमंत्री ने इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस-8 का दौरा किया और इस दौरान उन्हें संयंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने आईआईटी भिलाई की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने भारतनेट के चरण-2 के शुभारम्भ के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने जगदलपुर और रायपुर के बीच विमानन सेवाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, प्रमाण पत्र और चेक इत्यादि भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास सभी प्रकार की हिंसा का सबसे अच्छा हल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा में कहा कि करीब-करीब 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं का उपहार आज छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाईयो-बहनों को मैं समर्पित कर रहा हूं। ये सभी योजनाएं यहां रोजगार के नए अवसर बनाने वाली है। शिक्षा के नए अवसर पैदा करने वाली है। आवाजाही के आधुनिक साधन देने वाली है और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों को संचार की आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली है। कई वर्षों में हिन्दुस्तान में जब बस्तर की बात आती थी, तो, बंदूक, पिस्तौल और हिंसा की बात आती थी। आज बस्तर की बात जगदलपुर के हवाई अडडे से जुड़ गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों में 'ग्राम स्वराज अभियान' का व्यापक सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान (मिशन) को उन 115 आकांक्षी जिलों में काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें से 12 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। श्री मोदी ने उन फायदों का भी उल्लेख किया जो विभिन्न स्कीमों जैसे कि जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना और सौभाग्य की बदौलत इस राज्य में संभव हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए वन अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और देशभर में 'एकलव्य विद्यालय' खोले जा रहे हैं। ■

नया रायपुर भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी

नया रायपुर भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी है। नया रायपुर डिजिटल पहुंच वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी है। नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के तीन स्मार्ट नगरों में शामिल है जिसना चयन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किया गया है। अन्य दो शहर रायपुर और विलासपुर हैं। रायपुर को सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यापार, सेवा क्षेत्र, चिकित्सा व शिक्षा सेवाओं के हब के रूप में विकसित करने की योजना है। नया रायपुर के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र निम्न प्रणालियों का भी एकीकरण होगा।

- भूमि आवंटन, पानी की आपूर्ति, बिल भुगतान, आरटीआई शिकायतें आदि सेवाओं के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था।
- दिव्यांगजनों के लिए उपयोग में आसान अनुप्रयोग की विशेष व्यवस्था।
- परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष व्यवस्था।
- भवन अनुमति प्रक्रिया का स्वचालन।
- 24 x 7 घंटे बिजली व पानी की आपूर्ति।
- बुलेट और पीटीजेड कैमरे के द्वारा नगर की निगरानी।
- स्पीड डिटेक्शन और एएनपीआर के साथ ट्रैफिक नियमों का कार्यान्वयन।
- नगर प्रशासन में उत्तर दायित्व पर जोर।
- बिजली, पानी और सीवर प्रणाली का वास्तविक समय पर मूल्यांकन व प्रबंधन।
- संपत्ति व सेवाओं का अधिकतम उपयोग।
- व्यवसाय विश्लेषण, रिपोर्टिंग और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय व सटीक निर्णय।

इंटरनेट कवरेज में 75% से अधिक की वृद्धि

44.6 करोड़ यूजर हुए

पिछले चार वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसमें इंटरनेट कवरेज में 75% से अधिक की वृद्धि (25.1 करोड़ यूजर से 44.6 करोड़ यूजर), कुल टेली-घनत्व में 75% से 93% की वृद्धि और देश में दूरसंचार बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर सरकारी खर्च में छः गुना वृद्धि शामिल है।

इस संदर्भ में संचार और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि संचार मंत्रालय ने 'साफ नीयत सही विकास' की भावना से मजबूत डिजीटल संपर्क तथा नागरिक केंद्रित सेवाएं देकर पिछले चार वर्षों के दौरान देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रेरित किया है। श्री सिन्हा 12 जून को केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी तथा व्यापक स्तर पर भारत नेट जैसी डिजीटल संरचनाएं परियोजनाएं चलाकर तथा देश में डिजीटल खाई को पाटकर अविश्वास की भावना को दूर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि करना है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग में हमने विभाग के व्यवसाय को नया स्वरूप दिया है, जिसमें वित्तीय समावेश, नागरिक केंद्रित सेवाएं और अपने संचालन को नया ढांचा देने पर बल दिया गया है।

पिछले चार वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में निम्न क्रांतिकारी परिवर्तन हुए:

- देश में दूरसंचार बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर सरकारी खर्च में छः गुना वृद्धि-2009-14 के बीच 9,900 करोड़ रुपये से 2014-19 के बीच 60,000 करोड़ (वास्तविक + योजनागत)।
- कुल टेली-घनत्व में 75% से 93% की वृद्धि
- इंटरनेट कवरेज में 75% से अधिक की वृद्धि-25.1 करोड़ यूजर से 44.6 करोड़ यूजर हुए।
- मोबाइल बेस ट्रांससीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या दोगुनी से अधिक हुई- 7.9 लाख से लगभग 18 लाख।
- देशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कवरेज दोगुना हुआ- 7 लाख किमी से 14 लाख किमी।
- देश भर के उपभोक्ताओं को टैरिफ कटौती से लाभ मिला- औसत आवाज टैरिफ में 67% की गिरावट आई और औसत डेटा टैरिफ में 93% की गिरावट।
- ब्रॉडबैंड पहुंच में सात गुना वृद्धि- 61 मिलियन से 412 मिलियन ग्राहक हुए।
- दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह में पांच गुना बढ़ोतरी- 2015-16 में 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (दिसंबर 2017 तक)।

दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी तथा व्यापक स्तर पर भारत नेट जैसी डिजीटल संरचनाएं परियोजनाएं चलाकर तथा देश में डिजीटल खाई को पाटकर अविश्वास की भावना को दूर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि करना है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग में हमने विभाग के व्यवसाय को नया स्वरूप दिया है, जिसमें वित्तीय समावेश, नागरिक केंद्रित सेवाएं और अपने संचालन को नया ढांचा देने पर बल दिया गया है।

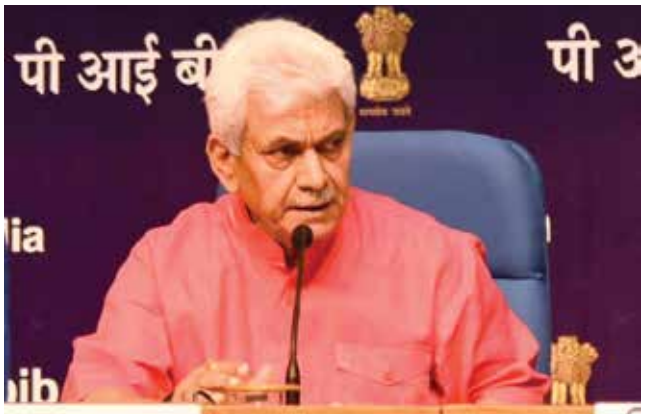

प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास का नारा भारत नेट जैसी ग्रामीण डिजीटल संरचना परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए बनी परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क रहित लोगों से संपर्क करने में दूरसंचार विभाग के प्रयास में दिखता है।

संचार मंत्री ने कहा कि विभाग ने टेक्नॉलोजी प्रेरित क्षेत्र में विश्व स्तर पर देश को अग्रिम श्रेणी में पहुंचाने के लिए अनेक अति सक्रिय कदम उठाए। हम 3 जी और 4 जी का मौका गंवा चूके, लेकिन 5 जी का अवसर नहीं गंवा सकते। नागरिकों के कल्याण के लिए नई

पिछले चार वर्षों में डाक विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

- औसत वार्षिक स्पीड पोस्ट राजस्व दोगुनी से अधिक- 2006-14 के बीच 788 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-18 के बीच 1682 करोड़ रुपये हुआ
- ई-कॉमर्स व्यवसाय से 2017-18 में राजस्व 415 करोड़ रुपये, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि के साथ।
- इस बढ़ते व्यापार भाग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग पार्सल निदेशालय की स्थापना की गई।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) लॉन्च करने के लिए जिला मुख्यालय डाकघरों में सह-स्थित 650 शाखाओं के साथ तैयारी, जिसमें बिना बैंकिंग और अंडर बैंकिंग के लाभ के लिए कई चैनलों में 360 डिग्री वित्तीय सेवा की पेशकश।
- डाक विभाग के 995 एटीएम दिसंबर 2016 से अन्य बैंकों के साथ अंतर-संचालित हैं; इन एटीएम पर 1.85 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए।
- डाकघरों में 1.18 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, 1.30 करोड़ खाते बैंकों में खोले गए।
- देशभर में सिर्फ 7 महीनों में 13,150 से अधिक डाकघरों में आधार नामांकन और अद्यतन केन्द्र खोले गए। इन केन्द्रों में 7 लाख से अधिक नामांकन और अद्यतन करने का कार्य पूरा किया गया।
- विदेश मंत्रालय के सहयोग से 213 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू किए गए। इसका उद्देश्य नागरिकों को 50 किलोमीटर के दायरे में पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना है। इन केन्द्रों में 10 लाख पासपोर्ट नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई।
- डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएल) पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी एक प्रमुख विशेषता है- निम्न अंशदान, उच्च प्राप्ति। ये दोनों बीमाएं डाक विभाग की उत्पाद हैं। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करना है।
- डाक जीवन बीमा का लाभ अब सिर्फ सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह सुविधा अब पेशेवरों (शिक्षक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, लेखाधिकारी) तथा एनएसई और बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों में काम करने वालों के लिए भी उपलब्ध है।
- ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों में औसत 56 प्रतिशत की वृद्धि। इससे 2.60 लाख ग्रामीण डाक सेवकों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा।
- विभाग में प्रौद्योगिकी निवेश दोगुना हुआ। निवेश 2010-14 के 434 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-18 में 1000 करोड़ रुपये हुआ।
- डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक 62000 मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण आबादी को वित्तीय और डाक सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सकें। इस सुविधा को 2018 के अंत तक 8.30 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इन उपकरणों (मोबाइल आदि) के माध्यम से 3800 करोड़ रुपये मूल्य के 3 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए।
- पोस्टमैन मोबाइल एप के जरिए वास्तविक समय पर सेवा प्रदान करने की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

टेक्नॉलोजी का लाभ उठाने के लिए सक्रिय नियोजन और निवेश प्रारंभ किए गए है। 5 जी इंडिया के लिए एक उच्चस्तरीय फोरम (एचएलएफ) स्थापित किया गया है, बजटीय सहायता से 5 जी टेस्ट बेड स्थापित किया जा रहा है। प्रगतिशील और दूरदर्शी प्रारूप राष्ट्रीय डिजीटल दूरसंचार नीति (एनडीसीपी) 2018 सार्वजनिक कर दी गई है और अगले कुछ वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं।

इन चार वर्षों में डाक विभाग ने परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य देश में डाकघरों का चेहरा बदल देना है। ठहरे हुए व्यवसाय से विभाग ने आगे बढ़ते हुए सफलतापूर्वक नागरिक केंद्रित सेवाएं लांच की है, जिनका लाभ देशव्यापी पहुंच और लोगों विशेषकर गैर मेट्रो क्षेत्र के लोगों, के विश्वास से मिलेगा।

गौरतलब है कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत पूरे देश के 1244 गांवों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मार्च, 2019 तक 10,000 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवम्बर, 2017 में बच्चों के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत छात्रों को डाक टिकट संग्रह को पसंदीदा कार्य बनाने तथा डाक टिकटों पर शोध करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 920 छात्रवृत्तियां उन बच्चों को दी जाती हैं, जो डाक टिकटों के प्रति रुचि दिखाते हैं।

श्री सिन्हा ने कहा कि दोनों ही विभाग तेजी से विकास कर रहे भारत के लाभों को देश के सुदूर हिस्सों में पहुंचाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम- डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास के अंतिम सिरे पर खड़ा व्यक्ति हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हम उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। यह पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचार-अंत्योदय के अनुरूप है। ■

संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन हेतु 9-10 जून को चीन के प्रमुख शहर किंगदाओ की सफल यात्रा की। भारत और पाकिस्तान के इस संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद यह पहला मौका है, जब भारतीय प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस संगठन को नाटो के समकक्ष माना जाता है। श्री मोदी के अलावा इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमिर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति श्री हसन रुहानी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री ममनून हुसैन भी शामिल हुए।

वर्ष 2001 में स्थापित इस संगठन के भारत के अलावा रूस, चीन, किर्गीज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान सदस्य हैं। एससीओ में अभी आठ सदस्य देश है जो दुनिया की करीब 42% आबादी और वैश्विक जीडीपी के 20% का प्रतिनिधित्व करता है।

शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने वुहान में श्री जिनपिंग के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता को भी याद किया। श्री मोदी और श्री जिनपिंग ने 27-28 अप्रैल को वुहान अनौपचारिक वार्ता में किये गये फैसलों के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा भी लिया।

सिर्फ भौगोलिक जुड़ाव नहीं, बल्कि लोगों का लोगों से जुड़ाव होना चाहिए: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने तथा आर्थिक वृद्धि, संपर्क सुविधाओं के विस्तार तथा आपस में एकता के लिए काम करने का आह्वान किया।

एससीओ के 18वें शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने संक्षिप्त नाम 'सिक्योर' के रुप में एक नयी अवधारणा रखी। इसमें 'एस' से आशय नागरिकों की सिक्योरिटी (सुरक्षा), 'ई' से इकोनामिक डेवलपमेंट (आर्थिक विकास), 'सी' से क्षेत्र में कनेक्टिविटी, 'यू' से यूनिटी (एकता), 'आर' से रेसपेटक्ट पार सावेरिनिटी एंड इंटिग्रिटी (संप्रभुता और अखंडता का सम्मान) और 'ई' से तात्पर्य (एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन) पर्यावरण सुरक्षा है।

इस क्षेत्र में परिवहन गलियारों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का मतलब सिर्फ भौगोलिक जुड़ाव से नहीं है, बल्कि यह लोगों का लोगों से जुड़ाव भी होना चाहिए।

चीन की 'एक क्षेत्र एक सड़क' (ओबीओआर) परियोजना पर परोक्ष रुप से आक्षेप करते हुए श्री मोदी ने कहा, ''भारत ऐसी हर परियोजना का स्वागत करता है जो समावेशी, मजबूत और पारदर्शी हो और जो सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हो।"

उल्लेखनीय है कि भारत ओबीओआर का लगातार कड़ा विरोध करता रहा है, क्योंकि यह विवादित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है।

श्री मोदी ने कहा, ''हम एक बार फिर उस पड़ाव पर पहुंच गए है जहां भौतिक और डिजिटल संपर्क भूगोल की परिभाषा बदल रहा है। इसलिए हमारे पड़ोसियों और एससीओ क्षेत्र में संपर्क हमारी प्राथमिकता है।"

उन्होंने कहा कि भारत एससीओ के लिए हर तरह का सहयोग देना पसंद करेगा, क्योंकि यह समूह भारत को संसाधनों से परिपूर्ण

मध्य एशियाई देशों से दोस्ती बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अफगानिस्तान को आतंकवाद के प्रभावों का 'दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण' बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में शांति के लिए जो साहसिक कदम उठाए हैं, क्षेत्र में सभी लोग इसका सम्मान करेंगे। उन्होंने इसी क्रम में ईद के मौके पर अफगानी नेता द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा का भी उल्लेख किया।

श्री मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का जो भी सफल निष्कर्ष होगा, भारत उसके लिए अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में केवल छह प्रतिशत एससीओ के सदस्य देशों से आते हैं और इसे आसानी से दोगुना किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ''हमारी साझा संस्कृतियों के बारे में जागरुकता

फैलाकर हम इसे (पर्यटकों की संख्या) आसानी से बढ़ा सकते हैं। हम भारत में एक एससीओ फूड फेस्टिवल और बौद्ध महोत्सव का आयोजन करेंगे।"

ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा साझा करने पर चीन राजी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा देगा। साथ ही, भारत अब चीन को बासमती से अलग दूसरी किस्मों के चावल का भी निर्यात करेगा। समझौते के तहत चीन बाढ़ के मौसम में प्रति वर्ष 15 मई से 15 अक्तूबर के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जल से संबंधित आंकड़े भारत को देगा। अन्य मौसम के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी वह आंकड़े उपलब्ध कराएगा। ■

प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद

स्वास्थ्य सभी तरह की सफलता और समृद्धि का आधार: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जून को वीडियो ब्रिज के माध्यम से देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने पांचवीं बार वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सभी तरह की सफलता और समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि भारत तभी महान और स्वस्थ होगा जब इसके 125 करोड़ नागरिक स्वस्थ होंगे।

श्री मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बीमारी न केवल परिवारों, विशेषकर गरीब और मध्यवर्ग के परिवारों, पर भारी आर्थिक बोझ डालती है, बल्कि हमारे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को रियायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसी इरादे से लांच की गई थी ताकि गरीब, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की रियायती औषधियों तक पहुंच हो और उनका वित्तीय बोझ कम हो।

सरकार ने पूरे देश में 3600 से अधिक जन औषधि केंद्रों को स्थापित किया है, जहां रियायती मूल्य पर 700 से अधिक जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों में दवाइयों की कीमत बाजार मूल्य की तुलना में 50-90 प्रतिशत कम हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या 5000 से ऊपर हो जाएगी। स्वास्थ्य स्टेंट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले स्टेंट खरीदने के लिए नागरिकों को अपनी संपत्ति बेचनी या बंधक रखनी पड़ती थी। सरकार ने स्टेंटों की कीमतों में काफी कमी की है, ताकि गरीब और मध्य वर्ग की मदद की जा सके। हार्ट स्टेंट की कीमत लगभग 2 लाख रुपये से घटाकर 29,000 रुपये कर दी गई है।

लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान सरकार ने घुटना प्रत्यारोपण कीमतों को 60-70 प्रतिशत घटा दिया है, जिससे लागत 2.5 लाख रुपये से घटकर 70,000-80,000 हो गयी है। अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 लाख घुटना प्रत्यारोपण होता है। इस हिसाब से घुटना प्रत्यारोपण में लागत की कमी से लोगों को 1500 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में 2.25 लाख रोगियों के लिए 22 लाख से अधिक डायलिसिस सेशन किया है। मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से 3.15 करोड़ से अधिक बच्चों और 80 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। अस्पतालों में अधिक बिस्तर, अधिक अस्पताल और अधिक डॉक्टर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 92 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और एमबीबीएस सीटों की संख्या 15,000 बढ़ाई गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुगम बनाने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लांच की। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ 10 करोड़ परिवार कवर किये जायेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वस्थ भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के कारण भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या 3.5 लाख हो गई है और स्वच्छता कवरेज 38 प्रतिशत बढ़ा है।

प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना से दवाइयों की कीमतें कम हो गई हैं और दवाइयां किफायती हो गई हैं। लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण में होने वाले खर्च में कमी से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग शुरू करने, योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की, ताकि स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद मिल सके। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

देहरादून (उत्तराखंड) में चौथे अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हजारों योगाभ्यासियों के साथ योग करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

किंगदाओ (चीन) में शंघाई सहयोग संगठन के सीमित सत्र में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

किंगदाओ (चीन) में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेते चीन के राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमिर पुतिन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA

साफ नीयत सही विकास

बंदरगाह के विकास में जबर्दस्त बढ़ोतरी

By 1/3rd

पिछले 4 वर्षों में प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज पर माल लादने और उतारने के समय में आई कमी

94 घंटे में 2013-14 — से — 64 घंटे में 2017-18

समय में आया कुल बदलाव (घंटे में)

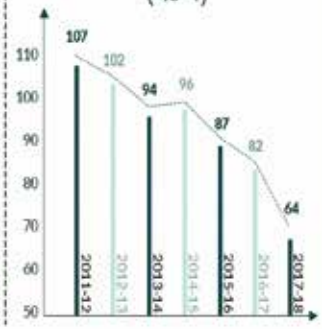

48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA

साफ नीयत सही विकास

राष्ट्र निर्माण के लिए जल शक्ति

पिछले 30 वर्षों में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग तैयार किए गए जबकि पिछले 4 वर्षों में इस सूची में 106 जलमार्ग जुड़े

प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो का ट्रैफिक (मिलियन टन में)

48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA

साफ नीयत सही विकास

न्यू इंडिया की तेजी से बढ़ती शक्ति

पिछले 4 वर्षों में अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार

WORLD ECONOMIC FORUM

इतिहास में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में प्रधानमंत्री मोदी से विश्व ने सुनी

लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाईजेशन और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में भारत को मिला प्रतिनिधित्व

WA

2017 में MTCR में शामिल होने के बाद, भारत 2018 में वासेनर एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया

48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA

साफ नीयत सही विकास

पूरी ताकत के साथ मातृभूमि की रक्षा

- इतिहास में पहली बार, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर अपना सामर्थ्य दिखाया
- लंबे समय से लंबित वन रैंक–वन पेंशन की मांग पूरी की गई
- सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तीव्र गति से जारी